प्रभात

अन्दर के पन्नों पर ...

★ बजट 2005-06 पर लेख ... 10
★ क्रान्तिकारी संगठनों पर सरकारी प्रतिबन्ध पर ... 15
★ कांग्रेसी नेताओं की दिवालिया राजनीति पर ... 16
★ पुलिसिया दमन और सरकारी सुधार कार्यक्रम ... 18
★ राजकीय दमन पर लेख ... 19
★ पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाइयों पर रिपोर्ट ... 20
★ दण्डकारण्य के संघर्ष-पथ पर ... 22
★ 'भूमकाल दिवस' की रिपोर्टें ... 26
★ 8 मार्च की रिपोर्टें ... 27

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 18 अंक - 2 अप्रैल- जून 2005 सहयोग राशि - 10 रुपए

डौला (धौड़ाई) हमले में शहीद हुए कॉमरेड्स मंगतू (सुनील), करुणा (पूनेम मोती), विनोद (कुमरम शिवाजी) और सोमारी को हमारा लाल-लाल सलाम !

जनयुद्ध को तेज कर शहीदों के सपनों को साकार बनाने का संकल्प लो !

दण्डकारण्य में जारी शत्रु दमन को परास्त कर जनयुद्ध को उन्नत स्तर पर विकसित करने के लक्ष्य से दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने अप्रैल 2005 से 'कार्यनीतिक जवाबी आक्रमण अभियान' चलाने का आह्वान किया है. इस अभियान का मकसद यह भी था कि दुश्मन के बलों द्वारा छेड़े गए 'ऑपरेशन एरिया डॉमिनेशन' को धूल चटा दी जाए और उनके हथियार छीनकर हमारी जन मुक्ति छापामार सेना को मजबूत बनाया जाए. इस अभियान के तहत पीएलजीए के तीनों बलों के योद्धाओं ने जनता की सक्रिय मदद से दुश्मन के पुलिस, एसटीएफ, सीएएफ और सीआरपीएफ के हत्यारे बलों के खिलाफ लगातार हमलों का सिलसिला छेड़ दिया. इन हमलों ने दुश्मन के नाक में दम कर रख दिया. खासकर हजारों जनता ने जन मिलिशिया की अगुवाई में अपने परम्परागत हथियारों से लड़ाई का जो नमूना पेश किया, वह अपने आपमें बेमिसाल है. जवाबी हमलों के इस अभियान के तहत दण्डकारण्य में अब तक दुश्मन के कम-से-कम 18 जवान मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और 70 से ज्यादा घायल हैं. जहां तक पीएलजीए के नुकसानों का सवाल है, डौला में हमारे चार साथी शहीद हो गए.

कॉमरेड मंगतू (सुनील)

17 मई 2005 को हमारी पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने बस्तर जिले के नारायणपुर तहसील के डौला (धौड़ाई) पुलिस कैम्प पर एक साहसिक हमला किया. अपने बहादुर कमाण्डरों के नेतृत्व में दर्जनों लाल योद्धाओं ने अपनी जान पर खेलकर इस हमले को अंजाम दिया. लेकिन हमले के पहले ली गई टोह के दौरान हुई कुछ तकनीकी खामियों की वजह से पूरी कोशिश के बावजूद भी यह हमला सफल न हो सका. दुश्मन की गोलियों की बौछार में कई कॉमरेड फंसी गए थे. कुछ कॉमरेडों को गोलियां लग गईं. हमारे प्यारे साथी कॉमरेड मंगतू (दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी व स्टेट मिलिटरी कमिशन का सदस्य तथा पीएलजीए की उत्तरी सब-जोनल कमान का कमाण्डर-इन-चीफ), कॉमरेड करुणा (प्लटून पार्टी कमेटी सदस्या व सेक्षन

कॉमरेड करुणा (मोती)

कॉमरेड विनोद (शिवाजी)

कॉमरेड सोमारी (रामो)

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाओ !

कमाण्डर), कॉमरेड विनोद (प्लटून पार्टी कमेटी सदस्य व सेक्षन कमाण्डर) और कॉमरेड सोमारी (पार्टी सदस्या) शहीद हो गए. इनके अलावा कुछ अन्य कॉमरेड घायल भी हुए. कॉमरेड्स करुणा, विनोद और सोमारी की मृत्यु मौके पर ही हुई, जबकि कॉमरेड मंगतू को गोली तब लगी थी जब वह बाकी कॉमरेडों को दुश्मन की गोलीबारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे. सीने में हुए गहरे जख्म के चलते अगले दिन, यानी 19 मई को उनकी मृत्यु हुई. शत्रु की भीषण गोलीबारी के चलते कॉमरेड्स करुणा और सोमारी की लाशें नहीं लाई जा सकीं. कॉमरेड विनोद और कॉमरेड मंगतू की अंत्येष्टि पीएलजीए के सैनिकों ने क्रान्तिकारी परम्पराओं से पूरे सम्मान के साथ पूरी की.

इस हमले में हमारे चार साथी भले ही शहीद हुए हों, पर पीएलजीए ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया. इस हमले के दौरान पीएलजीए योद्धाओं ने अदम्य साहस व शूरता का प्रदर्शन करते हुए एक साथ कई ठिकानों पर हमले करके दुश्मन के एक एसपी समेत करीब 22 पुलिस वालों को घायल कर दिया. इस हमले की तीव्रता को समझने के लिए यह जानना काफी है कि राज्य सरकार को अपने घायल जवानों को बचाने के लिए हेलिकॉप्टरों के लिए हाथ-पैर मारना पड़ा. पीएलजीए के बढ़ते हमलों से निपटने के लिए उसे केन्द्र से अतिरिक्त बलों की गुहार लगानी पड़ी. आइए, दण्डकारण्य आन्दोलन को मजबूती दिलाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की जीवनियों पर सरसरी नजर डालें.

कॉमरेड मंगतू

अदम्य योद्धा और जुझारू जन नेता

कॉमरेड मंगतू (38) का जन्म आन्ध्रप्रदेश के महबूबनगर जिले के एक गांव ..... में हुआ था. माता-पिता ने उनका नाम लिंगन्ना रखा था. दसवीं कक्षा के बाद इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए 1982-83 में जब वह अपना गांव छोड़कर हैदराबाद शहर आए थे तब उनका सम्पर्क रैडिकल छात्र संगठन (आरएसयू) से हुआ था. छात्रों की समस्याओं को लेकर आरएसयू द्वारा चलाए गए कई संघर्षों में उन्होंने बढ़-चढ़कर भाग लिया. उस समय हैदराबाद शहर में आरएसयू एक मजबूत संगठन के रूप में उभर रहा था. कई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर क्रान्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे थे. उन दिनों कॉमरेड सन्तोष रेड्डी (महेश), कॉमरेड दामोदर रेड्डी (संजीव) और कॉमरेड शंकर (ये सारे कॉमरेड अलग-अलग घटनाओं में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हो गए) हैदराबाद शहर के छात्र आन्दोलन को एक नई दिशा दे रहे थे. ऐसे महत्वपूर्ण समय में कॉमरेड कोमुरन्ना ने अपना सारा जीवन क्रान्ति के प्रति समर्पित करने का फैसला लिया और बहुत जल्द ही वह पार्टी सदस्य बन गए. 1984 में तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी की आन्ध्र राज्य कमेटी ने उन्हें तकनीकी काम सौम्प दिया था. तब से 1990 के मध्य तक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ यह काम किया. इन छह वर्षों के दौरान उन्हें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग नाम से रहना पड़ा. कई बार दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर उन्होंने हथियार, विस्फोटक सामग्रियां, हथगोले, आदि संघर्ष इलाकों में पहुंचा दिया था. इसी क्रम में वह एक अच्छे तकनीशियन और मैकानिक भी बने थे.

एक तरफ पार्टी द्वारा सौम्पे गए कामों को पूरा करते हुए ही उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना बढ़ाने की कोशिश की. 1985 में तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी में उत्पन्न आंतरिक संकट से भी वह विचलित नहीं हुए थे. एक सचेत पार्टी सदस्य की हैसियत से उन्होंने क्रान्तिकारी पक्ष का दृढ़ता से समर्थन किया और अवसरवाद का विरोध किया.

तकनीकी काम से सांगठनिक काम में...

1990 में पार्टी ने उन्हें तकनीकी काम से मुक्त करके सांगठनिक काम में भेजने का फैसला किया. इस फैसले को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बालाघाट-राजनांदगांव-भण्डारा इलाके में कदम रखा. तबसे वह जनता के बीच 'सुनील मरकाम' के नाम से काफी लोकप्रिय हो गए. इस इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन की शुरूआत 1990 में हुई. कॉमरेड सुनील के लिए भी जंगल नया था और आदिवासी जनता के बीच काम करने का अनुभव भी नया ही था. इसके बावजूद भी उन्होंने हर मुश्किल को पार करते हुए काम जारी रखा. इस तरह कॉमरेड सुनील बालाघाट-राजनांदगांव-भण्डारा क्षेत्र में क्रान्ति के बीज बोने वाले सबसे पहले छापामार दस्ते का सदस्य बन गए.

खासकर बालाघाट जिले में दुश्मन ने तीव्र दमनचक्र छेड़ दिया था ताकि वहां क्रान्तिकारी आन्दोलन को फैलने से रोका जा सके. लेकिन पार्टी के मार्गदर्शन में छापामार दस्ते ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर काम जारी रखा. दुश्मन के हमलों से बचते हुए जनाधार का निर्माण करते हुए आन्दोलन का निर्माण किया. एक साल के अन्दर ही एक दस्ते से दो-तीन दस्ते बने थे. पहले दस्ते के सदस्यों ने बाद में गठित दस्तों का नेतृत्व सम्भाला था. इस तरह कॉमरेड सुनील नवगठित 'टांडा' छापामार दस्ते का डिप्यूटी कमाण्डर बन गए. टांडा इलाका महाराष्ट्र का भण्डारा (अब गोंदिया) जिला, मध्यप्रदेश के राजनांदगाव (अब छत्तीसगढ़ में है) और बालाघाट जिलों के सीमान्त में था. दो राज्यों में आने वाले इन तीनों जिलों की उत्पीड़ित आदिवासी जनता में कॉमरेड सुनील काफी लोकप्रिय नेता बने थे. इस बेहद गरीब इलाके से सटकर मुम्बई-कोलकाता रेल लाइन गुजरती है. घने जंगलों से भरपूर इस इलाके में वन विभाग के अधिकारियों के जुल्मों की कोई सीमा नहीं थी. जनता उनके अत्याचारों से त्रस्त थी. घर बनाना, खेती करना, जंगल में गाय-बैल चराना, यहां तक कि दतौन तोड़ना भी उनकी नजर में गुनाह था. हर काम के लिए पैसे वसूलते थे. जो पैसा नहीं देते उन्हें अपराधी बनाकर कोर्ट-कचहरियों का चक्कर कटवाते थे. तेन्दुपत्ता व बांस कटाई के कामों में लोगों को बहुत कम मजदूरी देते

थे और 'पस्तूरी' के नाम से उनकी मेहनत का खुल्लमखुल्ला शोषण किया करते थे. जनता इन अत्याचारों और जुल्मों से मुक्ति चाहती थी पर सहारा देने वाला कोई न था. ऐसी स्थिति में वहां पर क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार हुआ. हर गांव में जनता ने क्रान्तिकारियों का अभूतपूर्व ढंग से स्वागत किया. कुछ गांवों में जन अदालत लगाकर भ्रष्ट और जुल्मी वन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे चलाए गए. जनता की मांग पर कुछ लोगों की पिटाई भी की गई. यह खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई. देखते ही देखते सारे वन अधिकारी गांव छोड़कर शहर भाग गए. यह सब भीषण पुलिसिया दमन के बीचोंबीच ही हुआ. जनता में संघर्ष का जोश पैदा हुआ. समूचे इलाके में हर जुबान पर क्रान्तिकारियों के चर्चे थे. ऐसे हालात में कॉमरेड सुनील ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और जनता को संगठित करने में उत्साह के साथ भाग लिया.

1992 में टांडा दल के तत्कालीन कमाण्डर कॉमरेड पवन को दुश्मन ने गिरफ्तार कर लिया था. तब कॉमरेड सुनील ने कमाण्डर की जिम्मेदारी ली. 1997 में उन्हें बालाघाट–भण्डारा संयुक्त डिवीजनल कमेटी का सदस्य चुन लिया गया. डिवीजनल कमेटी सदस्य के नाते भी उन्होंने टांडा इलाके का ही नेतृत्व किया. इस प्रकार करीब–करीब एक दशक तक उन्होंने टांडा इलाके के गोण्ड व बैगा आदिवासियों समेत समूची उत्पीड़ित जनता के दिलों पर राज किया.

बंगाल–बिहार–उड़ीसा इलाके में....

पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने बंगाल–बिहार (अब झारखण्ड)–उड़ीसा सीमान्त इलाके में एक और छापामार इलाके को विकसित कर उसे आधार इलाके में तब्दील करने का फैसला लिया. ठोस रूप से यह जिम्मेदारी बंगाल की राज्य कमेटी को दी गई. जंगल और लोहे के पहाड़ों के लिए जाने जाने वाले इस इलाके पर भारत का बड़ा पूंजीपति टाटा की पकड़ रहती है. यहां पर टाटा के न सिर्फ कई उद्योग स्थापित हैं, बल्कि टाटानगर शहर भी यहां से नजदीक ही है. इसलिए इस क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम जिले में ज्यों ही क्रान्तिकारियों ने कदम रखा तो समूचा सरकारी तंत्र ही उतर आया और दमन का भयानक सिलसिला छेड़ दिया. पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार कर हर हाल में वहां आन्दोलन को आगे बढ़ाने की ठान ली. और यह जिम्मेदारी कॉमरेड सुनील के भरोसेमन्द कंधों पर रखी. कॉमरेड सुनील ने तुरन्त ही वहां जाकर छापामार दस्ते की कमान अपने हाथों में ली और पहलकदमी के साथ जनता में काम करना शुरू किया. उनका मुख्य काम था वहां के स्थानीय कॉमरेडों को छापामार युद्ध के नियमों से परिचित कराना और उन्हें छापामार तौर–तरीकों में प्रशिक्षित करना. कॉमरेड सुनील ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई. साथ ही साथ, उन्होंने उस इलाके की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का गहरा अध्ययन भी किया. वहां की उत्पीड़ित जनता और दस्ता सदस्यों का भरोसा जीत लिया. कई नौजवान क्रान्तिकारियों को उन्होंने प्रशिक्षित कर दिया. (2003 में पूर्वी सिंहभूम जिले के लांगो गांव में दुश्मन द्वारा किए गए एक षड़यन्त्रपूर्ण हमले में पीएलजीए के जो 9 साथी शहीद हुए थे वे सब कॉमरेड सुनील से किसी न किसी रूप से प्रभावित थे.) कॉमरेड सुनील सिंहभूम इलाके में अपनी जिम्मेदारी पूरी करके करीब एक साल बाद दण्डकारण्य लौटे थे. दण्डकारण्य पार्टी के तीसरे अधिवेशन में उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया. बाद में नेतृत्वकारी शक्तियों के सन्तुलन और आन्दोलन की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्पेशल जोनल कमेटी ने उन्हें गड़चिरोली डिवीजन में स्थानान्तरित किया.

छापामार आधार–क्षेत्रों (गुरिल्ला बेस) के निर्माण–कार्य में ...

वर्ष 2001 में सम्पन्न तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी की 9वीं कांग्रेस में दण्डकारण्य को आधार इलाका बनाने के कार्यभार को अहम कार्यभार के रूप में स्वीकार किया गया. इसके तहत पहले हर डिवीजन में छापामार आधार–क्षेत्रों (गुरिल्ला बेसों) का निर्माण करने का फैसला लिया गया. इसके तहत दण्डकारण्य के सभी डिवीजनों में आवश्यक कार्ययोजनाएं तैयार की गईं. इस दौरान गड़चिरोली डिवीजन में शत्रु दमन लगातार बढ़ता ही जा रहा था. कॉमरेड सुनील ने दुश्मन के 'घेराव–दमन' अभियानों के बीचोंबीच ही जनता में काम किया. स्थानीय छापामार दस्तों और पार्टी की एरिया कमेटियों का उन्होंने बढ़िया मार्गदर्शन किया. 2002 नवम्बर में कॉमरेड सुनील को माड़ डिवीजन में स्थानान्तरित किया गया जहां उन्हें उन्नत सांगठनिक कार्यभार सौम्पा गया. उन्होंने 'मंगतू' के नाम से काम करते हुए बहुत जल्द ही लोगों के दिलों पर छा गए. जिन लोगों को बाहरी दुनिया 'पिछड़े' या 'असभ्य' कहकर तिरस्कार की नजर से देखती है, उन माड़िया लोगों को उन्होंने जनता की राजसत्ता की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ाया. हर पल उन्होंने जनता की राजनीतिक चेतना बढ़ाने का प्रयास किया. हर गांव में क्रान्तिकारी जन कमेटियों, यानी 'जनताना सरकार' का निर्माण करने तथा पार्टी व पीएलजीए की इकाइयों को मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी. एरिया पार्टी कमेटियों और ग्राम पार्टी कमेटियों के सुचारू संचालन के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया. इस दौरान पार्टी की निचली कमेटियों में उत्पन्न गैर–सर्वहारा रुझानों को समय पर पहचान कर जिम्मेवार कॉमरेडों को सुधारने की पूरी कोशिश की.

दुश्मन ने पुलिसिया दमन के साथ–साथ सुधार कार्यक्रमों को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए आन्दोलन पर चौतरफा हमला छेड़ दिया. आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण सुधारों के जरिए लोगों को भटकाना–बरगलाना भी आसान है, यही सोचकर सरकार ने 'विकास' की रट लगाते हुए बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रमों को शुरू किया. जनता का एक तबका इन सुधारों के पीछे की राजनीति को समझने में विफल होकर उन्हें पाना चाह रही थी. ऐसे में, कॉमरेड मंगतू ने स्थानीय पार्टी कमेटियों को सचेत कर जनता में सरकार के झूठे सुधार कार्यक्रमों के खिलाफ प्रचार चलाया. माड़ इलाके में कई सालों से डेरा जमाने वाली रामकृष्ण मिशन भी जनता को वर्ग संघर्ष से अलग करने की मंशा से झूठे सुधार कार्यक्रम शुरू किए थे. वे लोग जनता के बीच फटे–पुराने कपड़े बांटकर अखबारों में खूब वाहवाही लूट रहे थे. ऐसे में कॉमरेड मंगतू ने काफी सूझबूझ का परिचय देते हुए जनता को व्यापक पैमाने पर इकट्ठा करके रामकृष्ण मिशन की असलियत समझा दी. पार्टी, पीएलजीए व जन संगठन कार्यकर्ताओं

को उन्होंने सावधान किया कि सरकारी व गैर–सरकारी सुधार कार्यक्रमों के ढोंग के खिलाफ जनता को सचेत करना जरूरी है तथा इस मामले में किसी भी हालत में जनदिशा का उल्लंघन न किया जाए. दिसम्बर 2003 में सम्पन्न छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों तथा अप्रैल 2004 में सम्पन्न 13वीं लोकसभा चुनावों के समय कॉमरेड मंगतू ने डिवीजन में पार्टी व पीएलजीए के कतारों व जनता को राजनीतिक व फौजी रूप से संगठित कर 'चुनाव बहिष्कार' अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. माड़ इलाके में लगभग 100 प्रतिशत लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया. इन मौकों पर दुश्मन के सशस्त्र बलों के खिलाफ पीएलजीए के योद्धाओं ने कई हमले किए. कॉमरेड मंगतू ने कुछ हमलों में खुद कमान सम्भाली और जनता में आत्मविश्वास जगाया. 'जनताना सरकार' को गांव स्तर से बढ़कर इलाका व डिवीजन स्तर तक और राज्य स्तर तक फैलाकर देश भर में जनता की नई जनवादी सत्ता की स्थापना करने के लक्ष्य से उन्होंने हर पल काम किया. आज कॉमरेड मंगतू की शहादत की खबर सुनकर माड़ की समूची जनता को गहरा सदमा पहुंचा है.

एक सैन्य नेता के रूप में ...

मार्च 2003 में दण्डकारण्य स्पेशल जोन की प्लीनम सम्पन्न हुई जिसमें कॉमरेड मंगतू को स्पेशल जोनल कमेटी के वैकल्पिक सदस्य के रूप में सर्व सम्मति से चुन लिया गया. उसके बाद मई 2004 में उन्हें स्पेशल जोनल कमेटी में सहयोजित कर राज्य सैन्य आयोग का सदस्य बनाया गया. इस नाते उन्होंने पीएलजीए की उत्तरी सब–जोनल कमान के कमाण्डर–इन–चीफ की जिम्मेदारी भी ले ली. हालांकि वह लम्बे समय से सांगठनिक काम में ही थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फौजी जिम्मेदारी उठाई. वर्तमान हालात में फौज ही संगठन का मुख्य स्वरूप है और युद्ध ही संघर्ष का मुख्य स्वरूप है, इस सच्चाई को समझ लेते हुए उन्होंने खुद को एक फौजी नेता के रूप में उभारने का पूरा प्रयास किया.

2000 में पीएलजीए (तब पीजीए) के गठन के बाद जन मिलिशिया की सक्रियता काफी बढ़ गई. इस उभार को पहचान कर कॉमरेड मंगतू ने माड़ डिवीजनल कमेटी सदस्य के रूप में और बाद में एसजेडसी सदस्य के रूप में जन मिलिशिया के विकास पर मुख्य जोर दिया. परम्परागत हथियारों का पूरा उपयोग करते हुए दुश्मन के नजदीक तक जाकर उसका सफाया करने और उसके आधुनिक हथियार छीनकर पीएलजीए की शस्त्रास्त्र सम्पत्ति को मजबूत बनाने की जरूरत पर उनका जोर रहता था. खासकर माड़ इलाके के सैकड़ों युवाओं को उन्होंने दुश्मन से बेखौफ लड़ने की प्रेरणा दी.

दण्डकारण्य में लगभग हर क्रान्तिकारी का काम युद्ध से जुड़ा हुआ है. शुरू से ही दुश्मन इस आन्दोलन का सफाया करने हाथ धोकर लगा हुआ है. कॉमरेड मंगतू ने दुश्मन द्वारा किए गए कई हमलों को मुकाबला करने तथा दुश्मन पर हमला करने की कार्यवाहियों में भाग लिया. खासकर बालाघाट–भण्डारा डिवीजन में रहते समय उन्होंने कई फौजी कार्यवाहियों में शिरकत की. गोंदिया जिले (महाराष्ट्र) के दरेकस्सा पुलिस थाने पर 1991 में किए गए हमले में उन्होंने भाग लिया था. वह हमला सफल नहीं हो सका था. उसमें कॉमरेड ताराचन्द (दामोदर रेड्डी) शहीद हुए थे, जो कॉमरेड मंगतू के अच्छे दोस्त भी थे. बाद में जुलाई 1991 में बालाघाट जिले के सीतेफल गांव के पास पुलिस पर घात लगाकर हमला करके कॉमरेड ताराचन्द की शहादत का बदला लिया गया. उस हमले में 11 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों को घायल किया गया. उसमें कॉमरेड मंगतू स्काउट पार्टी के कमाण्डर के रूप में भाग लिया. 1996 में धीरी–मुरुम और नवागांव के पास दुश्मन द्वारा किए गए हमलों में कॉमरेड मंगतू डटकर खड़े थे. जहां भी और जब भी दुश्मन के साथ लड़ाई हुई तो कॉमरेड मंगतू प्रतिरोध में डटकर रहा करते थे. 17 मई 2005 की रात डौला कैम्प पर की गई शॉर्ट सरप्राइज अटैक में उन्होंने डिप्यूटी कमाण्डर के रूप में पीएलजीए योद्धाओं का नेतृत्व किया. जब दुश्मन की तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही थी और कई कॉमरेडों को गोलियां लग रही थीं तब उन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए कव्हर फायरिंग दी. उसी दौरान उन्हें सीने में गोली लगी थी. इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. पीएलजीए सैनिकों ने उन्हें उठाकर लाया और बचाने की पूरी कोशिश की जो सफल नहीं हुई. एक जुझारू सेना नायक के रूप में उन्होंने अपने ही कॉमरेडों के हाथों में अन्तिम सांसें लीं.

एक सीधा–सादा कॉमरेड

कॉमरेड मंगतू के स्वभाव व रहन–सहन की चर्चा किए बिना उनके जीवन का चित्रण अधूरा ही होगा. कॉमरेड मंगतू सीधे–सादे और सबसे आसानी से घुलमिल जाने वाले शख्स थे. वह जहां भी जाते वहां के लोगों और कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा बरताव किया करते थे. हमेशा हंसते–मुस्कराते रहने वाले कॉमरेड मंगतू चुटकुले सुनाकर और मिमिक्री करके साथियों का मनोरंजन भी करते थे. हालांकि जंगल में हर छापामार को मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों से दो–चार होना ही पड़ता है, पर कॉमरेड मंगतू कुछ ज्यादा ही इन बीमारियों का शिकार हो जाया करते थे. कई बार उन्हें मलेरिया–टाइफाइड से हफ्तों जूझना पड़ा. अपनी शहादत के दो माह पहले भी वह गंभीर रूप से बीमार हो गए थे. इसके बावजूद भी बहुत जल्द ही वह चंगा हो गए और दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़े. वह श्रम का सम्मान करते थे. जहां भी छापामारों का कैम्प लगता तो वह टाइम निकालकर रसोई में जाते थे और खुद खाना बनाते थे या दूसरों की मदद करते थे. छापामार दस्ते में किसी का हथियार खराब हुआ या किसी का हथगोला ठीक नहीं है तो वह खुद पेचकश–पाना निकालकर उसकी मरम्मत में जुट जाते थे. सभी सदस्य उन्हें प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा जमीन से जुड़े नेता रहे. गुस्सा, घमण्ड, आदि चीजें उनमें कभी नहीं देखी गईं.

कॉमरेड मंगतू अध्ययन के मामले में एक गंभीर छात्र हुआ करते थे. मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन उन्होंने आखिर तक जारी रखा. पार्टी की ओर से जारी की जाने वाली सरकुलरों और दस्तावेजों पर वह रोचक बहस करते थे. उन पर रचनात्मक तरीके से अमल के लिए आवश्यक कदम उठाते थे. वह देश–विदेश की खबरें ध्यान से सुनते थे. दुनिया के सम–सामयिक विषयों पर वह अच्छी जानकारी रखते थे. हर मुद्दे पर पार्टी का दृष्टिकोण अपने साथियों को समझाया करते थे. पार्टी द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं के अलावा हर राजनीतिक पत्रिका पर वह पैनी नजर रखते थे.

उनका व्यवहार साफ–सुथरा रहता था. अपनी तरफ से जब कोई गलती होती है तो वह अपनी आत्मालोचना बिना किसी लाग–लपेट के पेश करते थे. खासकर बालाघाट डिवीजन में 1996 में जब नेतृत्वकारी कॉमरेडों में पितृसत्तात्मक विचारधारा हावी हो जाने से समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, तब कॉमरेड मंगतू ने संघर्ष किया. खुद अपने अन्दर के पितृसत्तात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ अन्य साथियों और नेतृत्व के खिलाफ सही आलोचना पेश की. इस प्रकार उस समय डिवीजन में पैदा हुए संकट को दूर करने और कॉमरेडों में एकता कायम करने में कॉमरेड मंगतू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की.

कॉमरेड मंगतू हमेशा अमर रहेंगे...

आज कॉमरेड मंगतू हमारे बीच में नहीं हैं. पर उनके संघर्ष, जुझारूपन, निस्वार्थ भावना, मेहनती स्वभाव, अध्ययनशीलता आदि आदर्श हमारे सामने हैं. उनकी मृत्यु से दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को निश्चित रूप से काफी नुकसान हुआ है. पार्टी और पीएलजीए ने एक महान जन नेता और बहादुर कमाण्डर खो दिया. उनकी यादगार सभा में बोलते हुए एक कॉमरेड ने कहा, ''जब मंगतू ने आखिरी सांस ली तब उनकी आंखें पूरी तरह खुली थीं... जैसे वे कह रही थीं कि जब तक समाजवाद और बाद में साम्यवाद की स्थापना नहीं हो जाएगी तब तक मंगतू आराम नहीं करेंगे.'' आइए साथियो, हम अपने आंसुओं को पोंछकर कॉमरेड मंगतू के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प दोहराएं.

कॉमरेड करुणा

जुझारूपन का दूसरा नाम

कॉमरेड करुणा का जन्म दन्तेवाड़ा जिले के बीजापुर तहसील के गंगलूर रेंज स्थित ग्राम मेट्टापाड में हुआ था. घर में उनका नाम था मोती पूनेम. वह अपने माता–पिता की पांच संतानों में पहली थीं. हालांकि उनका गांव गंगलूर पुलिस थाने से काफी नजदीक ही था, लेकिन क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए वह एक मजबूत गढ़ था. गांव में सभी जन संगठन सक्रिय रहते थे. कॉमरेड करुणा क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस) की सदस्या बनकर गांव की महिलाओं को गोलबन्द करती थीं. इस सिलसिले में वह पार्टी की क्रान्तिकारी राजनीति से प्रभावित होकर अपना पूरा जीवन क्रान्ति के लिए समर्पित करने को तैयार हो गईं. यह समझते हुए कि नव जनवादी क्रान्ति को सफल किए बिना महिला की असली मुक्ति नहीं हो सकती, वह क्रान्ति में कूद पड़ी. स्थानीय पार्टी इकाई भी उनके काम से प्रभावित थी. 1997 में वह दस्ते में भर्ती होकर छापामार बन गईं. सबसे पहले उन्हें बासागूडेम दस्ते में रखा गया था.

कॉमरेड करुणा शारीरिक व मानसिक रूप से एक चुस्त–दुरुस्त छापामार महिला थीं. इसे देखते हुए 1998 में पार्टी की दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी ने करुणा को विशेष छापामार दस्ते में ले लिया. एक साल तक उन्होंने विशेष छापामार दस्ते में काम किया. इस क्रम में पार्टी ने उन्हें पार्टी सदस्यता प्रदान की. 1999 में उन्हें नव गठित पलटन–2 में सदस्या के रूप में चुन लिया गया. फौजी कार्यवाहियों में उनकी पहलकदमी तथा नेतृत्वकारी गुणों को देखते हुए पहले उन्हें सेक्षन डिप्यूटी कमाण्डर और बाद में सेक्षन कमाण्डर बनाया गया. 28 जुलाई 2004 को दण्डकारण्य में पीएलजीए की पहली कम्पनी का निर्माण हुआ. कम्पनी के अन्दर एक पलटन में महिलाओं का एक विशेष सेक्षन गठित करने का फैसला हुआ था. कॉमरेड करुणा को इस विशेष सेक्षन की कमाण्डर बनाया गया.

1997 से लेकर 2005 तक अपने 9 साल की क्रान्तिकारी जिन्दगी में कॉमरेड करुणा ने कई हमलों में भाग लिया. वह एक तपी हुई लड़ाकू महिला थीं जिन्होंने यह सच्चाई फिर एक बार साबित की कि युद्ध के क्षेत्र में भी महिला पुरुष से किसी भी मायने में कम नहीं है. 1998 में बासागूडेम के निकट तोर्रेम गांव में दुश्मन पर किया गया एम्बुश कॉमरेड करुणा का पहला एम्बुश था. उस हमले में 16 पुलिस वाले मारे गए थे और 17 घायल हुए थे. करुणा उस सफल एम्बुश में अपनी भागीदारी के लिए बेहद गर्व महसूस करती थीं. बाद में कोंगुपल्ली, वाकुलवाही आदि हमलों में उन्होंने सहायक टीम की सदस्या बनकर भाग लिया. उत्तर बस्तर डिवीजन के बजरंगबली, पश्चिम बस्तर के तीगेला, मोतुकुपल्ली, उसिकापटनम, सालपल्ली आदि एम्बुशों में भाग लेकर उन्होंने अपने लड़ाकूपन का उम्दा प्रदर्शन किया. पुलिस थानों पर किए गए रेडों में भी उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन किया. ताल्लागूडेम, मोटू, वेदिरे, गीदम आदि थानों पर किए गए रेडों में वह थीं. गीदम रेड में एक एम्बुश बैच की डिप्यूटी कमाण्डर के रूप में उन्होंने भाग लिया. इन सारे हमलों में उन्होंने सदस्या या टीम लीडर के रूप में भाग लिया. उनकी मृत्यु से पीएलजीए ने एक सक्षम व जुझारू योद्धा, खासकर महिला मोर्चे से उभरी सैन्य नायिका खोई.

कॉमरेड करुणा का एक खास गुण यह था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं फेरा. पार्टी ने उन्हें जब भी और जो भी काम सौम्पा या उन्हें जहां भी भेजा तो उन्होंने कभी न नहीं कहा. फौजी कार्यवाहियों के दौरान भी नेतृत्व उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौम्पता वह उसे पूरी निष्ठा से पूरी करती थीं. पिछले साल जब दण्डकारण्य में पहली कम्पनी का निर्माण करने का फैसला हुआ और उसमें उनका चुनाव हुआ तो कॉमरेड करुणा ने इस फैसले को खुशी से स्वीकार किया. हमारी पीएलजीए नए–नए फॉर्मेशनों में बढ़ते हुए नई–नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़े, इसी कामना के साथ वह पीएलजीए कम्पनी में शामिल हुईं. डौला हमले में उन्हें दुश्मन के अड्डे में घुसकर उसका सफाया करने वाली हमलावर टुकड़ी में कॉमरेड करुणा का चुनाव हुआ. वह बेखौफ होकर अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ीं.

पार्टी और पीएलजीए में पितृसत्तात्मक रुझानों के खिलाफ भी कॉमरेड करुणा ने तीखा संघर्ष किया. जब कुछ पुरुष साथियों ने उन पर अनुचित तरीके से शादी का दबाव डाला तो उन्होंने पलटन की बैठक में उनकी आलोचना की. वह महिलाओं पर पुरुषों के किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करती थीं. अपनी शहादत के

एक–दो माह पहले ही उन्होंने एक साथी योद्धा के साथ शादी की थी. चूंकि वह साथी दूसरी इकाई में काम करते थे इसलिए शादी के बाद वे मुश्किल से एक हफ्ता साथ रहे होंगे. चूंकि दोनों ने ही अपनी निजी जिन्दगी से बढ़कर क्रान्ति के कार्यभारों को तवज्जो दिया, इसलिए दुश्मन के खिलाफ कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण अभियान को सफल बनाने हेतु शादी के बाद अपने–अपने इलाकों की ओर रवाना हो गए. क्रान्तिकारी साहचर्य का मुख्य पहलू कुरबानी ही होता है, इस बात को कॉमरेड करुणा ने फिर एक बार साबित कर दिया.

कॉमरेड करुणा का एक और आदर्शपूर्ण गुण उनका मेहनती स्वभाव था. वह पलटन में रहे या कम्पनी में, वह सदस्या रहे या कमाण्डर के पद पर, हर समय कठिन व बोझिल कामों में करुणा आगे रहा करती थीं. उनकी यादगार में आयोजित सभा में बोलते हुए उनके कम्पनी कमाण्डर ने उन्हें इस प्रकार याद किया : ''मैं करुणा को जब भी याद करता हूं तो उसका रूप मेरे मन में सिर पर किसी गठरी के साथ ही आता है. क्योंकि पलटन या कम्पनी में जब भी कोई अतिरिक्त बोझा रहता तो वह जरूर और सबसे पहले उठा लिया करती थीं. उनकी जिन्दगी से हमें यह मेहनती गुण जरूर सीखना चाहिए..'' उसी सभा में बोलते हुई एक महिला कमाण्डर ने यूं कहा.. ''हम लड़ाकू महिलाओं को जब–जब ऐसा लगता था कि हमारा आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ है तो हम करुणा की तरफ देखती थीं. हमारे लिए वह न सिर्फ प्रेरणा का स्रोत थीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत भी थीं.'' निश्चित रूप से दण्डकारण्य की क्रान्तिकारी महिलाओं को कॉमरेड करुणा की शानदार शहादत से जबर्दस्त प्रेरणा मिलेगी.

17 मई को डौला में किए गए हमले में कॉमरेड करुणा ने हमलावर टुकड़ियों में से एक की डिप्यूटी कमाण्डर के रूप में नेतृत्व किया. पुलिस कैम्प में घुसने के दौरान उनके पैरों में गोलियां लगी थीं. इसके बावजूद उन्होंने अपने मुंह से कोई आवाज तक नहीं की क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थीं कि ऐसा करने से दुश्मन का हौसला बढ़ सकता है. बहते खून और अकथनीय दर्द को उन्होंने धैर्य के साथ होंठों के पीछे सह कर अन्तिम सांस ली. एक सदस्य से शुरू कर सेक्षन कमाण्डर तक उभरने वाली कॉमरेड करुणा की मृत्यु से पीएलजीए को बड़ा नुकसान हुआ है. आइए, हम इस लड़ाकू व बलिदानी महिला के मकसद को पूरा करने का संकल्प लें और उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाएं.

कॉमरेड विनोद

सच्चा जन–सेवक व जांबाज लड़ाकू

25 वर्षीय कॉमरेड विनोद आन्ध्रप्रदेश के आदिलाबाद जिले के बजारहतनूर मण्डल के गांव डेडरे के एक मध्यम वर्गीय गोण्ड आदिवासी परिवार में जन्मे थे. घर पर उनका नाम था शिवाजी कुमरम. 1987–88 से इस इलाके में तत्कालीन पीपुल्सवार पार्टी ने अपना कामकाज शुरू किया था. विनोद का गांव उस इलाके में क्रान्तिकारी आन्दोलन के मजबूत गढ़ों में एक हुआ करता था. कॉमरेड विनोद का पूरा परिवार आन्दोलन के साथ जुड़ा हुआ था. बचपन से ही विनोद क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रभावित था. उनकी एक दीदी 1990 में पार्टी की पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनी थीं जो फिलहाल दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होकर जेल में कैद हैं. इस प्रकार क्रान्तिकारी माहौल में पले–बढ़े कॉमरेड विनोद स्कूल में पढ़ते वक्त रैडिकल छात्र संगठन का सदस्य बन गए. 7वीं तक पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी. बाद में कुछ समय तक गांव के जन संगठन में सक्रिय रूप से काम किया.

1998 के शुरू में उन्होंने पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में छापामार जिन्दगी में कदम रखा. 6 महीने तक उन्होंने स्थानीय बोध छापामार दस्ते के सदस्य के रूप में काम किया. बाद में डिवीजनल कमेटी ने उन्हें उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड .... का सुरक्षा गारद नियुक्त किया. गारद के रूप में दो साल तक काम करने के बाद उनकी फौजी क्षमता, अनुशासनबद्धता, मेहनती स्वभाव आदि देखकर उन्हें पलटन में भेज दिया गया. उस समय उत्तर तेलंगाना में शत्रु दमन काफी तीखा था. इसके बीचोंबीच कॉमरेड विनोद पहले सेक्षन डिप्यूटी कमाण्डर और बाद में कमाण्डर के रूप में उभरे थे.

पुलिसिया दमन के चलते शत्रु के दलालों को सजा देने की जरूरत के मद्देनजर कॉमरेड विनोद को डिवीजन के एक्शन टीम में ले लिया गया. पुलिस के हमलों में उत्तर तेलंगाना में पार्टी नेताओं समेत कई साथी शहीद हो रहे थे. ऐसे कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग हिम्मत हारकर दुश्मन के सामने घुटने टेक रहे थे. पूरे उत्तर तेलंगाना में जो हालात थे वही आदिलाबाद जिले में भी थे. कल तक अपने साथ रहकर दुश्मन के हमले में जान गंवाने वाले नेतृत्वकारी कॉमरेड जब शहीद हो जाते हैं तो उनके आदर्शों और अधूरे मकसद को पूरा करने का बीड़ा उठाना कोई मामूली काम नहीं था. लेकिन कॉमरेड विनोद ने यह काम करके दिखाया. दुश्मन के सामने घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर क्रान्ति के साथ धोखा करने वाले गद्दारों को जनता में पर्दाफाश किया. आदिवासी जनता को क्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग करने की मंशा से दुश्मन द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार का जवाब देने और जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की. मुश्किल समय में भी मुस्कान बिखेरते रहने वाले कॉमरेड विनोद सभी का चहेता हुआ करते थे. वह काफी संवेदनशील शख्स हुआ करते थे. उन्हें जब कोई दुख या तकलीफ होती तो भी वह उसे बाहर प्रदर्शित नहीं करते थे. जिन लोगों की वजह से उन्हें नाराजगी होती थी उन लोगों से भी अच्छी तरह घुलमिल जाया करते थे.

2003 अक्टूबर में कोरापुट अभियान के लिए केन्द्रीय रीजियन के तीनों जोनों से कॉमरेडों को इकट्ठा किया गया था जिनमें कॉमरेड विनोद भी एक थे. उस दौरान दुश्मन ने भी हमारे बलों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी. कई हमले किए थे. ऐसे समय भी, नया इलाका और अनजान भाषा होने के बावजूद कॉमरेड विनोद बिना किसी हिचकिचाहट के अभियान में भाग लिया. कोरापुट हमलों को सफल

बनाने में कॉमरेड विनोद ने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया. कोरापुट अभियान के सफल होने के बाद उन्हें उत्तर तेलंगाना से दण्डकारण्य में तबादला करते हुए एनटीएसजेडसी द्वारा किए गए फैसले को उन्होंने तहेदिल से स्वीकार किया. इलाका चाहे जो भी हो पार्टी के फैसले को मानते हुए क्रान्तिकारी क्रियाकलापों को बिना रुके जारी रखना उन्होंने अपना अहम फर्ज माना. दण्डकारण्य में पहली बार गठित पीएलजीए कम्पनी में उन्होंने खुशी से सेक्षन कमाण्डर की जिम्मेदारी स्वीकार की. यहां की स्थानीय भाषा सीखकर स्थानीय कॉमरेडों का स्नेह जीत लिया. वह बीमार हालत में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के प्रति हमेशा तत्पर रहा करते थे. डौला हमले में हमलावर टुकड़ी का सदस्य बनकर उन्होंने भाग लिया. दुश्मन का सफाया करने के जोश के साथ जब वह आगे बढ़ रहे थे तभी उनकी मृत्यु हुई. आदिलाबाद जिले में एक जमाने में लुटेरी सरकार के खिलाफ बगावत का परचम बुलन्द करने वाले लोक नायक कुमरम भीम की विरासत को जारी रखते हुए कुमरम शिवाजी (विनोद) ने भी जनता मुक्ति के लिए अपनी जान कुरबान की. आइए, हम कॉमरेड विनोद की संघर्षमय विरासत को आगे बढ़ाने की कसम खाएं.

कॉमरेड सोमारी

पीएलजीए की आदर्शवान सैनिक

पार्टी में 'सोमारी' और 'सरस्वती' के नामों से जाने जाने वाली पोट्टम रामो का जन्म दन्तेवाड़ा जिला, बीजापुर तहसील, गंगलूर रेंज के पूम्बाड गांव में हुआ था. माता-पिता की पांच संतानों में वह सबसे बड़ी थीं. पूम्बाड एक ऐसा गांव है जिसने जनता की मुक्ति के लिए लड़ने वाले कई वीर पैदा किए. दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन के वर्तमान इतिहास में लाल अक्षरों में अंकित होने वाले दर्जनों गांवों में पूम्बाड भी एक है. इस गांव में पैदा होकर पीएलजीए में भर्ती होने वाले कई साथी आज कमाण्डर बने हैं. इस तरह के गांव में पल-बढ़ने वाली कॉमरेड सोमारी को अनुशासन जैसे घुट्टी में ही पिलाया गया हो. गांव में क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन में काम करते हुए वह धीरे-धीरे पार्टी की उम्मीदवार सदस्या बन गईं.

2001 में वह गंगलूर छापामार दस्ते में भर्ती हो गईं. दस्ते में रहकर गांव-गांव घूमते हुए उन्होंने जनता का विश्वास जीत लिया. कॉमरेड सोमारी के दृढ़ संकल्प व अनुशासन को देखते हुए पार्टी ने उन्हें सदस्यता प्रदान की. 2003 में उन्हें पलटन-4 में स्थानान्तरित किया गया. बाद में 2004 में वह नव निर्मित कम्पनी की सदस्या बन गईं. मोदुकुपल्ली, सालापल्ली एम्बुशों तथा गीदम रेड में उन्होंने भाग लिया. अकाल हमलों और मुखबिरों को दण्डित करने में भी वह शामिल थीं.

अनुशासन का पालन करने में कॉमरेड सोमारी एक आदर्शवान छापामार थीं. एक सैनिक के रूप में नेतृत्व के आदेशों का पूरी तरह से पालन करना, जो जिम्मेदारी उसे दी जाती उसी तक सीमित रहना, सभी के साथ मेल-जोल रखना, गलती करने वाले कॉमरेडों की आलोचना करना, गलतियां सुधारने में साथियों की मदद करना - आदि गुण कॉमरेड सोमारी से हम सभी को सीखना चाहिए.

कॉमरेड सोमारी की एक और खूबी यह थी कि फौजी कसरत-कवायद में वह सक्रिय रूप से भाग लेती थीं. इस मामले में वह सबसे अव्वल थीं. फौजी ड्रिलों में उनकी सोच यही रहती थी कि कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं पड़ना चाहिए. हर आइटम को वह बिना किसी संकोच के कर लेती थीं. अगर कोई आइटम उन्हें ठीक से करना नहीं आता था तो वह अगले दिन सुबह सबसे पहले ही, यानी रोलकाल के पहले ग्राउण्ड में आतीं और उसे तब तक प्राक्टीस करती थीं जब तक कि वह उनकी पकड़ में नहीं आता. अगर एक दिन वह किसी कारण से ग्राउण्ड में नहीं आतीं तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई कीमती चीज उनके हाथ से छूट गई हो. छोटे-मोटे दर्द या किसी गौण कारण से ग्राउण्ड में गैर-हाजिर होना उन्हें बिलकुल नहीं भाता था.

कॉमरेड सोमारी के चेहरे पर मुस्कान कभी मिटती ही नहीं थी. वह सभी के साथ बिना किसी संकोच के बातचीत करती थीं. फौजी तौर पर उनकी दक्षता को देखते हुए डौला हमले में उन्हें एक हमलावर टुकड़ी में रखा गया था. वह एक महत्वपूर्ण टीम में अपने चुनाव को लेकर काफी खुश थीं. कॉमरेड करुणा के साथ वह बड़े उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी थीं. दुश्मन के साथ हुई बेरहम लड़ाई ने कॉमरेड सोमारी को हमसे छीन लिया. छोटी-सी उम्र में उन्होंने शहादत की सर्वोच्च बुलन्दियां छू लीं. डौला शहीदों की यादगार सभा में बोलते हुए एक कॉमरेड ने यूं कहा, ''जंग हमारा पेशा नहीं है, जंग हमारा शौक भी नहीं है. पर इस जहां से जंग का नामोनिशान तक मिट जाए, इसीलिए हम मजबूर होकर जंग में उतर चुके हैं. हम अवाम की ताकत पर यकीन करने वाले हैं और हमारी जंग अवाम-ए-जंग है. इसीलिए जब हम कोई लड़ाई हार जाते हैं तो उतना उदास भी नहीं होते और जब हमें जीत मिलती है तो घमण्ड से चूर नहीं हो जाते. आज डौला में हमें कामयाबी नहीं मिली और हमारे अनमोल कॉमरेड शहीद हो गए. तो क्या हुआ? हार और जीत जंग के दो पहलू हैं. आज हम हार गए तो हम इसके गुण-दोषों का जायजा लेंगे और अगली लड़ाइयों की योजना बनाते समय उन बिन्दुओं पर खास ध्यान देंगे जिनके चलते हमें हार का मुंह देखना पड़ा. और शहीदों की कुरबानियां तो हमारी जमा पूंजी है जहां से हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी. हम उनके सैकड़ों-हजारों वारिस पैदा करेंगे. हमें डौला में मिली पराजय को लेकर चिन्तित होते समय मानपुर, गीदम, कोरापुट, सारंडा, वाकुलवाही जैसी कामयाब लड़ाइयों को भी जरूर याद करना चाहिए. हम निश्चित रूप से सफल लड़ाइयां लड़ते जाएंगे. डौला में खून बहाने वाले कॉमरेड्स मंगतू, करुणा, विनोद और सोमारी की कुरबानी व्यर्थ नहीं जाएगी. हम वर्ग दुश्मनों के खिलाफ दुगुनी हुई नफरत से आगे बढ़ेंगे और डौला शहीदों के खून का बदला जरूर लेंगे.''

7 जून 2005

श्रद्धांजली

जन मुक्ति छापामार सेना का जांबाज सिपाही कॉमरेड मासा को लाल सलाम

अरुणांचल जब अरुण वर्ण से रंग जाएगा,

तब प्रकाशित होने वाले अमर शहीदों की सूची में

अंकित होगा, सबसे पहले, कॉमरेड मासा, तेरा ही नाम !

11 अक्टूबर 2004 को गड़चिरोली के ग्यारहपत्ती कैम्प के पुलिस बलों को नुकसान पहुंचाने की योजना के तहत बूबी ट्रैप्स बिछाते समय हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होकर कॉमरेड मासा उर्फ राहुल उर्फ सुधीर ने शहादत को प्राप्त किया। कॉमरेड मासा टिप्रागढ़ दस्ते का जांबाज सिपाही था।

अरुणांचल से दण्डक वनों तक

अरुणांचलप्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाला 23 वर्षीय सुधीर बचपन से ही साहसी था। अपने बचपन में मां के साथ मारपीट करने वालों को उसने बड़ा होकर मरम्मत की थी। अन्याय न सहने के उसके स्वभाव ने उसे नगा आन्दोलनकारियों के नजदीक लाया। एनएससीएन खपलांग गुट के साथ जुड़कर उसने अपनी विद्रोही जिन्दगी की शुरूआत की थी। लेकिन पुरानी पीपुल्सवार पार्टी में कार्यरत अपने मामा का प्रभाव उस पर बचपन से ही था। 10वीं पास करने के बाद 2003 जनवरी में वह अपने मामा से मिलने इस्पात नगरी पहुंचा। रक्त सम्बन्ध ने उसे इस्पात नगरी तक लाया जबकि वर्ग सम्बन्धों की राजनीति ने उसे दण्डकारण्य की राह दिखाई। पार्टी में भर्ती होने के लिए वह इंतजार करता रहा। पार्टी का आदेश मिलते ही वह जंगल पहुंचा। 10 मार्च, 2003 को माड़ के पहाड़ों में प्रवेश करते ही उसने अपना नाम बदला। सुधीर से मासा बनकर गड़चिरोली के टिप्रागढ़ दस्ते में शामिल हो गया। मई 2003 में दस्ते पर जब फायरिंग हुई, नया होते हुए भी उसने साहस का परिचय दिया।

कॉमरेड मासा निर्भीक एवं निडर था। पीएलजीए का अनुशासित सिपाही था। पार्टी ने जब उसके सामने विशेष सैनिक कार्यवाही में भाग लेने का प्रस्ताव रखा तो वह तुरन्त तैयार हो गया। भारत के क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास में सुनहरा अध्याय के रूप में अंकित कोरापुट हमले में कॉमरेड मासा ने राजेश बनकर भाग लिया और पार्टी द्वारा सौंपे गए कार्य को बखूबी अंजाम दिया। इस हमले की कार्यवाही में ड्राइवर की जिम्मेदारी को सूझबूझ के साथ निभाया।

कोरापुट के सफल हमले से लौटने के बाद पुनः टिप्रागढ़ दस्ते में शामिल मासा अप्रैल 2004 में कोटी ऐम्बुश में भाग लिया। दुश्मन को खत्म करने के लिए वह हमेशा बेताब रहता था। उसके मुंह से कभी यह सुनने को नहीं मिलता था कि वह फलां काम नहीं करना चाहता है। पार्टी के द्वारा सौम्पे गए हर कार्य को पूरा करने के लिए वह आतुर रहा करता था। दस्ते के सदस्यों के साथ घुल-मिलकर रहता था। उन्हें पढ़ाने, लिखाने में रुचि रखता था। जंगल में प्रवेश करते ही वह जिस कैम्प में पहुंचा था, उसी में उसने छापामारों को कराटे प्रशिक्षण देना शुरू किया। तब से वह जहां भी रहता, कराटे प्रशिक्षण जरूर देता था।

13 अक्टूबर 2004 को सम्पन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव बहिष्कार करने वाली जनता पर पुलिस ने दमन बढ़ा दिया था। प्रतिरोध कार्यवाही के तहत स्थानीय पार्टी के आदेश पर कॉमरेड मासा ने अपने और साथियों के साथ ग्यारापत्ती पुलिस स्टेशन के नजदीक (500 मीटर) बूबी ट्रैप्स बिछाने गया था। लेकिन दुर्घटनावश बूबी ट्रैप्स का विस्फोट हो गया जिसमें कॉमरेड मासा एवं एक अन्य कॉमरेड गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कॉमरेडों को कुछ दूर में रखकर बाकी छापामार कमाण्डर को सूचित करने चले गए। कुछ इंतजाम के साथ दोबारा जब छापामार घायल साथियों के पास पहुंचे, तब तक मासा चल बसा था। क्रान्तिकारी लक्ष्य को हासिल करने अपनी जान कुरबान करने वाले कॉमरेड मासा की जिन्दगी हमारे लिए सदा प्रेरणादायक रहेगी। गड़चिरोली डिवीजन की पार्टी कमेटी ने कॉमरेड मासा को मरणोपरान्त पार्टी सदस्यता प्रदान की। ★

क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन की नेता कॉमरेड सन्तोषी

माड़ डिवीजन के कोह्कामेट्टा इलाके के कच्चापाल गांव की निवासी थीं कॉमरेड सन्तोषी। वह करीब 6 साल पहले केएएमएस की सदस्या बनी थीं। बाद में वह गांव की कमेटी में सदस्या चुन ली गईं। पार्टी के मार्गदर्शन में संगठन के काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपने गांव में एक मिसाल पेश की। पार्टी और संगठन द्वारा सौंपा गया हर काम वह उत्साह के साथ पूरा किया करती थीं। नव जनवादी क्रान्ति के तहत ही नारी मुक्ति सम्भव है और समाजवादी व्यवस्था ही नारी की सम्पूर्ण मुक्ति के सपने को साकार बना सकती है – इस राजनीति से प्रेरित कॉमरेड सन्तोषी गांव में और अपने इलाके में आयोजित होने वाली हर क्रान्तिकारी गतिविधि में बढ़-चढ़कर भाग लेती थीं। क्रान्ति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और काम में उनके अनुशासन को देख स्थानीय पार्टी ने उन्हें वर्ष 2000 में पार्टी सदस्यता प्रदान की।

आधार इलाके के लक्ष्य से जारी दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने और दुश्मन के हमले को परास्त करने के लिए इस इलाके में पीएलजीए के विभिन्न बलों ने दुश्मन पर कई हमले किए। कॉमरेड सन्तोषी ने जन मिलिशिया के साथ मिलकर ऐसे कई हमलों में भाग लेकर दुश्मन की नींद हराम कर दी। सन्तोषी के माता-पिता ने आदिवासी परम्पराओं के साथ एक रिश्तेदार के साथ उनकी शादी करानी चाही तो सन्तोषी ने संगठन का सहारा लिया। उन्होंने अपने संगठन में चर्चा करके उस व्यक्ति के साथ शादी के लिए लोगों का अनुमोदन हासिल किया जिससे वह प्यार करती थीं। पति-पत्नी दोनों भी गांव में जारी क्रान्तिकारी गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया करते थे। हाल ही में 10 फरवरी 2005, यानी भूमकाल संघर्ष के वर्षगांठ दिवस पर इस नौजवान और लड़ाकू महिला की दुःखद मृत्यु हुई। प्रसव के समय दुर्भाग्य से उनकी नवजात बच्ची के साथ-साथ उनकी भी मौत हो गई। इस इलाके के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए, खासकर माड़ डिविजन केएएमएस के लिए यह एक नुकसान है। लेकिन यह निश्चित है कि माड़ की सैकड़ों-हजारों महिलाएं कॉमरेड सन्तोषी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हंसिया-हथौड़ा, तीर-धनुष आदि हथियारों से आगे बढ़ेंगी – भूमकाल की विरासत को ऊंचा उठाएंगी। ✶

क्रान्तिकारी समर्थक कॉमरेड विनोद कुमार कोर्राम

दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा इलाके के बंडा गांव के निवासी थे विनोद कुमार कोर्राम। शुरू से ही वह लोकयुद्ध के जबर्दस्त समर्थक रहे। जनवरी 2005 में बीमारी के कारण कॉमरेड विनोद हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए। 35 वर्षीय विनोद का जन्म एक शिक्षक परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने ही गांव में अपने पिता से ही प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में कोंटा कस्बे में मेट्रिक पूरी की। 1992 में उन्हें पोस्टमैन की नौकरी मिली तो वह अपने गांव में आकर वहीं बस गए। दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन जब से शुरू हुआ तभी से यह गांव क्रान्तिकारी गतिविधियों के केन्द्रों में से एक रहा। शुरू से विनोद का पूरा परिवार गुप्त रूप से और खुलेआम भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और हर प्रकार का सहयोग दिया करता था। सहज ही अपने छात्र जीवन से ही विनोद पार्टी की क्रान्तिकारी राजनीति से प्रेरित हुए थे।

खासकर पिछले 10 सालों से उन्होंने क्रान्तिकारी साहित्य को नियमित रूप से पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों उनका अध्ययन गहराता गया, त्यों-त्यों वह पार्टी की ओर ज्यादा खिंचते गए। जब अपने भाइयों में से एक ने पार्टी में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम करने का फैसला लिया तो खुद विनोद ने उसे पार्टी के जिम्मेवारों के पास लाकर छोड़ दिया। जब परिवार के बाकी सदस्य भी किसी न किसी तरीके से पार्टी के कामों में हाथ बंटा रहे थे, तो विनोद को इस पर रत्ती भर आपत्ति भी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उन्हें उत्साहित किया। पुलिस दमन जब तीखा हुआ था तब भी उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। अपने भाइयों से कहते थे कि सावधानी के साथ, दुश्मन से बचते हुए गतिविधियों को जारी रखा जाए। दुश्मन की हलचलों की हरेक खबर वह पार्टी को नियमित रूप से पहुंचाया करते थे।

अपनी जिन्दगी में कॉमरेड विनोद ने पार्टी के लिए अनेकों प्रकार के काम किए। कई बार तो अपनी नौकरी और जान की भी परवाह न करते हुए क्रान्ति के लक्ष्य को सफल बनाने की खातिर कई जोखिम भरे काम किए। अपने इलाके के बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों को पार्टी की ओर आकर्षित करने और उन्हें संगठित करने में कॉमरेड विनोद का बढ़िया योगदान रहा। वह कई लोगों को लाकर पार्टी से परिचय करवा देते थे।

5 नवम्बर 2004 को इसी इलाके के गोल्लापल्ली में पुलिस ने दो शिक्षकों और एक छात्र को झूठी झड़प में मारा था। इसके पीछे सरकार का इरादा साफ था – पार्टी के प्रति बुद्धिजीवियों और कर्मचारियों के समर्थन को तोड़ देना। सारे शिक्षक व छात्र समुदाय में दहशत फैलाने के लिए ही पुलिस-प्रशासन ने इन जघन्य हत्याओं को अंजाम दिया था। लेकिन कॉमरेड विनोद इन हत्याओं से डरे नहीं थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। इन हत्याओं के खिलाफ कोंटा कस्बे में सरकारी प्रतिबन्ध के बावजूद जबर्दस्त विरोध रैली निकालने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस रैली में करीब 20 हजार लोगों ने भाग लिया।

कॉमरेड विनोद की असामयिक मौत से इस इलाके के क्रान्तिकारी आन्दोलन के लिए एक बड़ा झटका लगा। हम अपना सिर झुकाकर कॉमरेड विनोद को श्रद्धांजली पेश करते हैं और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। और हम यह संकल्प लेते हैं कि कॉमरेड विनोद समेत तमाम शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे। ✶

बजट 2005-06

यूपीए का माकपा-समर्थित बजट

जनता के सख्त खिलाफ - बड़े पूंजीपतियों के सामने नत मस्तक

पिछले साल संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) के सत्तारूढ़ होने के बाद से वह जन विरोधी तथा साम्राज्यवाद/बड़े पूंजीपतियों के अनुकूल नीतियों को लगातार लागू करता आ रहा है. इस वर्ष का बजट भी इसी की कड़ी कही जा सकती है. बावजूद इसके कि वह 'वामपंथ' पर निर्भर है, वह जिस तेजी से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एजेन्डे पर अमल कर रहा है वह भाजपा-नीत एनडीए से भिन्न कतई नहीं है. दरअसल यूपीए सरकार जिस रफ्तार से 'आर्थिक सुधार' पेश कर रही है वह सम्भवतः भाजपा से भी ज्यादा है. यह न सिर्फ उसकी दो केन्द्रीय बजटों में, बल्कि विभिन्न कांग्रेस-शासित राज्यों की सरकारों द्वारा लागू नीतियों से भी स्पष्ट हो रहा है.

महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने मुम्बई में जितनी बर्बरता से झोंपड़पट्टियों पर बुलडोजर चलाकर 3 लाख से ज्यादा लोगों को बेघरबार कर दिया, इस बात का एक उदाहरण मात्र है. कांग्रेसिया बुलडोजरों ने न सिर्फ पहले से गरीबी से त्रस्त लोगों के घरों और झोंपड़ियों को ढहा दिया, बल्कि उनके तमाम सामान को भी तबाह कर दिया. दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार तो बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पूरा शहर ही बेच डालने पर तुली हुई है. हाल ही में उसने दिल्ली जल बोर्ड को ही बेच डालने की षड़यंत्रकारी प्रक्रिया शुरू कर दी. जहां तक आन्ध्रप्रदेश की कांग्रेस सरकार का सवाल है, उसने न सिर्फ अपनी मुफ्त बिजली नीति उलट दी, बल्कि नक्सलवादियों के खिलाफ उसकी क्रूरता का स्तर तेलुगुदेशम सरकार से भी बढ़ गया है. हर दूसरे दिन मुठभेड़ की खबरें मीडिया में आ रही हैं.

हालांकि कांग्रेस अपनी नीतियों को प्रगतिशील लगने वाली शब्दावली में लपेट देने में माहिर है. दोगलापन, धोखाधड़ी, पाखंड, पीठ में छुरा भोंकना, आदि शुरू से ही कांग्रेसवाद के लक्षण रहे हैं. सुर्जीत, बासू, बुद्धा, येचूरी, आदि 'मार्क्सवादी' कांग्रेस से लम्बे समय से दोस्ती करके अब कांग्रेसवाद के अच्छे छात्र बन चुके हैं. हमेशा जहरीली मुस्कान बिखेरने वाले चिदम्बरम ने दरअसल इस बजट के जरिए गरीब जनता के दिलों में छुरा घोंप दिया है. माकपा ने इस बजट की तारीफ करके जनता को ठगने में कांग्रेस की विचारधारात्मक मदद की है. उसने छुरे पर मीठी परत चढ़ाने का ही काम किया. पिछले बजट में भी इसे साफ तौर पर देखा गया था. पिछला बजट भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लिए कम और धन्ना सेठों, खासतौर पर साम्राज्यवादियों के लिए ज्यादा फायदेमंद था. इसके बावजूद भी सत्तारूढ़ संशोधनवादियों ने उसकी जमकर सराहना की थी.

वर्तमान बजट (और बजट-पूर्व कवायद) 'आर्थिक सुधारों' को आगे बढ़ाने में पिछले बजट और एनडीए से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है. कराधान और अन्य नीतियों में इसने महत्वपूर्ण ढांचागत बदलाव पेश किए हैं ताकि साम्राज्यवाद-शासित 'सुधारों' को तेजी से अमल करने मदद की जा सके. जहां वे राज्य स्तर पर वैट (मूल्य संवर्धन कर) को जबर्दस्ती लागू करवा रहे हैं, वहीं उन्होंने दूसरी तरफ कराधान नीति में ढांचागत सुधार पेश किए हैं जिससे बुनियादी तौर पर मजदूर, कर्मचारी, मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे. जिस दिन बजट पेश किया गया, ठीक उसी दिन रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों बेचने का पूरा नक्शा ही पेश किया. सभी मजदूर कानूनों को संशोधित करने की दिशा में इस बजट में और ज्यादा कदम उठाए गए हैं ताकि मजदूर वर्ग का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा सके. उत्खनन, बीमा, पेन्शन और फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी की सम्पूर्ण पैठ के लिए इसने एक योजना पेश की है. इसके पहले बड़ी दवा कम्पनियों और मोन्सान्टो जैसी विदेशी बीज कम्पनियों के आदेशों पर पेटेन्ट कानून को संशोधित किया गया था और एक नया बीज कानून पारित किया गया था. इससे भारत का कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर बेहद बुरा असर पड़ेगा. अन्ततः, इस बजट में और हाल ही में उठाए गए अन्य कदमों से वे केन्द्र सरकार के हाथों सारे वित्तीय अधिकारों को केन्द्रित कर संविधान के मौजूदा नाम मात्र के संघीय ढांचे को भी उलटने की कोशिश की जा रही है. वे यह काम न सिर्फ 'वैट' के जरिए, बल्कि बजट के तीन दिन पहले जारी की गई 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अमल के जरिए करने जा रहे हैं.

इस बजट के ढांचागत बदलावों में अधिकांश की बुनियादी रूपरेखा केलकर टास्क फोर्स (कर सुधारों पर बनी कमेटी) की सिफारिशों तथा वित्तीय जिम्मेदारी बजट प्रबन्धन (एफआरबीएम) कानून - 2003 (बजट घाटों पर नियंत्रण के लिए बना कानून) में सम्मिलित है. इन दोनों को भाजपा/एनडीए के शासन में साम्राज्यवादियों और दलाल पूंजीपतियों के निर्देशों पर पारित किया गया था. इसका मतलब है, भाकपा/माकपा द्वारा समर्थित कांग्रेस शासन में उन कानूनों और सिफारिशों पर वास्तविक रूप से अमल किया जा रहा है जिन्हें कि भाजपा ने पारित किया था!!!

आइए, अब हम इस बजट के कुछ मुख्य लक्षणों पर नजर डालें -

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा जारी

कृषि क्षेत्र के प्रति लगातार जारी उपेक्षा के चलते पिछले साल खाद्य अनाज के उत्पादन में फिर एक बार 3% गिरावट दर्ज की गई. वर्ष 2004-05 के लिए किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक इस वर्ष मानसून में 13% भारी कमी हुई है. कृषि तथा उससे सम्बन्धित गतिविधियों में कुल मिलाकर महज 1% वृद्धि दर्ज हुई है. लेकिन, चूंकि अर्थव्यवस्था के लिए कृषि इतनी महत्वहीन हो गई है, इसलिए

जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर अभी भी 6% से थोड़ी ही ज्यादा रह गई है. दरअसल पिछले कुछ सालों (2001–02) से जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में 3.5% गिरावट और आई है जिससे अब वह सम्पूर्ण जीडीपी का 21% ही रह गया, इसके बावजूद भी कि 70 फीसदी आबादी इस पर निर्भर रहकर जीवन गुजारती है. इसके अलावा, आज खाद्य अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता उतनी ही है जितनी कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले थी. 1980 के दशक में वह सालाना 178 किलो हुआ करती थी, जो आज केवल 155 किलो है.

खाद्य अनाज के उत्पादन में पिछले साल हुई गिरावट से गरीब लोग ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में 60 लाख टन और दलहनों में 20 लाख टन की भारी–भरकम कमी हुई थी. इसके बावजूद भी सरकार ने खाद्य सब्सिडी (रियायत) में 3,000 करोड़ की कटौती की है. दूसरी तरफ उसने उर्वरक सब्सिडी में 4,000 करोड़ रुपए की भारी बढ़ोत्तरी की है ताकि बड़े पूंजीपतियों द्वारा ऊंचे दामों पर आयात किए गए वस्तुओं की क्षतिपूर्ति की जा सके. दूसरे शब्दों में कहें तो जनता का पैसा साम्राज्यवादियों द्वारा कच्चे मालों, जिन्हें कि उर्वरक उद्योगों को निर्यात किया जाता है, पर बढ़ाए गए दामों के बदले खर्चा जा रहा है.

इस बजट में ग्रामीण विकास और रोजगार गारन्टी को लेकर लम्बी–चौड़ी बातें भले ही कही गई हों, लेकिन बहुत कम पैसे आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री ने 'भारत निर्माण विजन' की जोर–शोर से घोषणा की जिसके तहत एक करोड़ ग्रामीण नौकरियों का सृजन किया जाएगा बताया गया. लेकिन उन्होंने इसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी. ठोस आवंटन जितने भी किए गए हैं वे सभी धनी किसानों की मदद करने वाले और कृषि–व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले हैं. 'भारत निर्माण' के तहत – अगामी चार सालों में एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन को सिंचाई के दायरे में लाने, 74 हजार बस्तियों में पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराने, 1 लाख 25 हजार गांवों और 2 करोड़ 30 लाख घरों में बिजली देने आदि बड़ी–बड़ी बातें जो कही गई हैं वो सब एक सफेद झूठ है क्योंकि इसके लिए बहुत कम पैसे आवंटित किए गए हैं. और ग्रामीण रोजगार और रोजगार गारन्टी योजना के दुःस्वप्नों के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने सिर्फ इतना ही कहा, ''जब इसे पूरी तरह लागू करेंगे, तब इससे लाखों गरीब परिवारों को जीविका मिलेगी. मैं वादा करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए मैं पैसों का इंतजाम करूंगा''. इसका मतलब है हमें सिर्फ वादे मिलते हैं, न कि वास्तविक कोष. उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य के युक्तीकरण की बात भी की जिसका असली उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य को पूरी तरह से हटा देना.

दूसरी तरफ 1,000 आबादी वाले हर गांव (आदिवासी गांवों के मामले में 500) में सड़क विकास के लिए ठोस रूप से पैसे आवंटित किए गए. इसका मूल उद्देश्य है काउन्टर–इंसर्जेन्सी (छापामार आन्दोलन के खिलाफ) कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद की गहरी पैठ के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना. इस बजट ने विश्व बैंक के सूक्ष्म–वित्त योजना (माइक्रो–फाइनेन्स स्कीम) को प्रोत्साहित करके साम्राज्यवाद द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया. वित्त मंत्री ने कहा, ''अगले वित्त वर्ष में करीब ढाई लाख स्व–सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ा जाएगा.'' निश्चित रूप से यह सब सरकार की कम–तीव्रता वाले संघर्ष की योजनाओं का हिस्सा है जिन्हें कि देश में बढ़ रहे कृषि क्रान्तिकारी आन्दोलनों के खिलाफ लागू की जा रही हैं. इस दिशा में उठाया गया एक और कदम यह है कि ग्रामीण इलाकों में दूरसंचार नेटवर्क के निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए की भारी राशि आवंटित की गई है. सम्पन्न लोगों और कृषि–व्यापार की सेवा करने के साथ–साथ पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों को तेजी से उतारने के लिए भी यह बहुत जरूरी थी.

इस बजट में ''विविधीकरण और उसकी कार्ययोजना की जरूरत पर जोर देने'' के नाम पर कृषि–व्यापार पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया गया है. फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध उत्पादों, कुक्कुट–पालन, मछली–पालन, दलहनों और तिलहनों पर मुख्य जोर रहा करेगा. एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की जाएगी जिसके लिए 630 करोड़ रुपए की भारी राशि आवंटित की गई है. कृषि विविधीकरण में शोध के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि बीज तैयार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नई नस्लें ला सकें. और एक सबसे पागलपन भरी योजना में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि ग्रामीण इलाकों में सूचना प्रौद्योगिकी को फैलाया जा सके और ''2007 तक हर गांव में ग्रामीण ज्ञान केन्द्र खोला जा सके.'' इसके अलावा शक्तिशाली चीनी मिलों को बैंक दर से 2% कम ब्याज का भुगतान करने की छूट देकर उन्हें 200 करोड़ रुपए का उपहार दे दिया गया.

दूसरी तरफ भारतीय कृषि पर नए पेटेन्ट और बीज कानूनों का बेहद घातक असर पड़ने वाला है. इन दोनों को डब्ल्यूटीओ ने आगे बढ़ाया है. इन दोनों कानूनों का उद्देश्य है किसानों द्वारा संरक्षित बीजों की जगह अन्तर्राष्ट्रीय बीज उद्योग द्वारा तैयार बीजों को लाना और किसानों को अपने बीजों का इस्तेमाल करने और आदान–प्रदान करने से रोक देना. इसमें कोई शक नहीं कि ''बीज पुलिस'' भी बन जाएगी जो किसानों को और ज्यादा प्रताड़ित किया करेगी.

जब हम इस बजट को गौर से देखते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रस्तावित उद्देश्यों को परखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि माकपा और अन्य लोगों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर अमल का जो ढिंढ़ोरा पीटा जा रहा है वह सब एक बड़ा ढोंग है. इससे चारों तरफ मुश्किलें ही बढ़ेंगी जबकि ग्रामीण सम्पन्न लोगों के एक ऐसे छोटे तबके को फायदा मिलेगा जो कृषि–व्यापार से सांठगांठ करके लाभ उठाएगा. आश्चर्य की बात नहीं, बजट पेश करने के महज तीन दिन बाद सरकार ने अनुवांशिक तरीके से परिवर्तित बीटी काटन (कपास) पौधे लगाने की अनुमति दे दी, बावजूद इसके कि आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में ये बीज बुरी तरह विफल हो चुके थे जिससे वहां के किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ा था.

अमीरों को बांटने के लिए जनता को लूटना

साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत जन कल्याण पर टिके रहने की जो लम्बी–चौड़ी बातें भाकपा/माकपा कर रही हैं वह एक और ढोंग है. कुल सब्सिडियों के मद में सिर्फ 2% (918 करोड़ रुपए) की बढ़ोत्तरी की गई है, मुद्रास्फीति को गिनती में लेने से असल में इसमें कम से कम

3 से 5% की कटौती ही की गई है. इसमें अमीरों और बड़े पूंजीपतियों को लुटाई गई सब्सिडी भी शामिल है. सरकारी आंकड़ों में मुद्रस्फीति की दर भले ही 5% के आसपास है, जनता के लिए वास्तविक दर इससे कहीं ज्यादा है. तो सब्सिडी मद का वास्तविक मूल्य एक बड़ा घाटा है. 2004–05 का आर्थिक सर्वेक्षण खुद ही बताता है कि आलू, चाय, चीनी, नमक, बाजरा, गुड़, कोयला, आदि चीजों के मामले में मुद्रास्फीति दर दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है. पिछले चंद महीनों में ही चीनी के दामों में करीब 25% की बढ़ोत्तरी हुई है. बुनियादी जरूरतों के दामों में आई उछाल ने गरीबों पर बुरी मार की है. आज मिट्टी तेल काला बाजार में 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है, जबकि शहरों में गरीबी रेखा से ऊपर और नीचे का विभाजन के बाद राशन व्यवस्था में मिट्टी तेल बिकता ही नहीं.

जहां बुनियादी जरूरती चीजों के दामों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, वहीं विलासिता की चीजों पर उत्पादन शुल्क में कटौती की जा रही है. उदाहरण के लिए, एयर कन्डीशनरों पर उत्पादन शुल्क 24% से 16% तक और कारों पर 15% से 10% तक घटा दिया गया. एविएशन ईंधन (हवाई जहाजों में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल) पर भी शुल्क घटा दिया गया जिससे प्रत्येक उड्डयन कम्पनी को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा फायदा मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ इस बजट में डीजिल और पेट्रोल पर 50 पैसा प्रति लीटर का रोड टैक्स बढ़ा दिया गया. इससे गरीब और मध्यम तबकों के लोगों की जेब से 8,000 करोड़ रुपए की भारी राशि निकाल ली जाएगी. सार्वजनिक परिवहन में तथा किसानों द्वारा पम्प चलाने में डीजिल का ही इस्तेमाल व्यापक रूप से होता है. इससे एक तरफ परिवहन का खर्च बढ़ जाएगा तो दूसरी तरफ पहले से मुश्किलों में फंसे किसानों के सामने और मुसीबत खड़ी हो जाएगी.

हालांकि आयकर में कुछ रियायतें देकर मध्यम वर्गों को तोहफे दिए गए हैं, पर कहीं और कटौतियां करके इसे सन्तुलित किया गया. आयकर छूट में आने वाली राशि 50,000 रुपए से 1 लाख तक बढ़ा दी गई. सालाना ढाई लाख रुपए तक कमाने वालों पर कर 10% घटा दिया गया. इससे मध्यम वर्ग पैसा बचा सकेंगे. लेकिन अब कुछ निश्चित सार्वजनिक क्षेत्र की बचत योजनाओं में मानक कटौतियों, जो पहले उपलब्ध थीं, को हटाकर किसी भी नोटिफाइड बचत योजना में एक लाख रुपए तक निवेश करने पर एक साझा कर मुक्त भत्ता लागू कर दिया गया. बचत योजना में किए गए इस बदलाव से निवेशक पर कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन देश के साझा कोष, बीमा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घुसने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए यह एक भारी तोहफा है. वे अब उन बचत राशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगी जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के कर मुक्त योजनाओं में जाया करती थीं. दरअसल इस फैसले से एक और घोषणा यह जुड़ी हुई है कि निजी बैंकों में अब 74% विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी की अनुमति होगी. इसके अलावा इन सभी कदमों से सबसे ज्यादा फायदा अमीरों को ही होगा क्योंकि अब कर में छूट सभी के लिए होगी, जबकि पहले सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला करती थी जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है. इसके अलावा, इन उलझी हुई बचत योजनाओं से वरिष्ठ नागरिकों को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें 20,000 रुपए का जो टैक्स रियायत (वापसी) मिला करती थी वह अब उन्हें नहीं मिलेगी. उनकी कुल आय में कमी होगी.

इस बजट ने नौकरी पेशा के लोगों को मिलने वाले 'फ्रिंज बेनिफिट्स' पर भारी भरकम 30% टैक्स (मौजूदा दरों में सबसे बड़ी दर) लगाया. इसमें हरेक कर्मचारी कल्याण योजना को शामिल किया गया, जिसमें बड़ी कम्पनियों के साथ–साथ व्यक्तिगत मिल्कियतें भी आती हैं. चूंकि 'फ्रिंज बेनिफिट्स' में आने वाली चीजों में स्वास्थ्य, परिवहन, यात्रा, हेल्थक्लब, खेल की सुविधाएं, मनोरंजन, आदि को शामिल किया गया है, इसलिए इससे सभी कर्मचारियों के कल्याण और आय पर कड़ी मार पड़ेगी. 'फ्रिंज बेनिफिट्स' पर लगाए गए 30% के भारी टैक्स के चलते अब ज्यादातर कम्पनियां या तो अपनी कल्याण योजनाओं में कटौती करेंगी या फिर अपने कर्मचारियों से यह राशि वसूलने की कोशिश करेंगी. दोनों परिस्थितियों में कर्मचारी ही घाटे में होंगे. मजे की बात यह है कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, आदि को मिलने वाले भारी 'फ्रिंज बेनिफिट्स' को नहीं छूया गया. बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय को (सोनिया के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के साथ–साथ) आवंटित राशि में 12% बढ़ोत्तरी करके 16.13 करोड़ कर दिया गया – यानी 4.5 लाख रुपए प्रति दिन!!!

सबसे बड़ा और स्पष्ट तोहफा मिला है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ–साथ बड़े पूंजीपतियों को. निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) और उत्पादन शुल्कों में 5% कटौती से बड़े पूंजीपतियों को सिर्फ एक साल के अन्दर 14,350 करोड़ का भारी–भरकम फायदा मिलने वाला है. अचरज की बात नहीं कि बड़े पूंजीपतियों के सारे सरगना इस बजट की तारीफ करते, चिदम्बरम को गुलदस्ते पेश करते नहीं थक रहे हैं.

निगम कर को 35% से 30% तक घटाने से बड़े पूंजीपति घरानों को पूरा 5,150 करोड़ रुपए का फायदा होगा. शीर्ष उत्पादन शुल्क को 20% से 15% तक घटा दिया गया (1991 में यह 120% से ज्यादा था जिसे हर बजट में घटाते आ रहे हैं). कपड़ा उद्योग की मशीनों पर शुल्क 20% से 10% तक घटा दिया गया. सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी 217 चीजों और हार्डवेयर सामग्रियों पर आयात शुल्क समाप्त किया गया. ईंधनों और पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क 15/20% से महज 10% तक घटा दिया गया. शुल्कों में की गई इन कटौतियों से बड़े पूंजीपतियों को आगामी वर्ष 9,200 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा होगा. **इन कटौतियों से सिर्फ एक कम्पनी – रिलएन्स को 1,7 00 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है !**

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों को फायदे ही फायदे

ऊपर बताए गए तोहफों के अलावा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों को कई अन्य भारी फायदे भी हैं.

बैंकों को तगड़ी विदेशी वित्तीय कम्पनियों के हवाले करने पर इस बजट में मुख्य रूप से जोर दिया गया. जिस दिन बजट पेश किया गया ठीक उसी दिन रिजर्व बैंक ने भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की योजना तथा रिजर्व बैंक द्वारा चयनित निजी बैंकों में मालिकाना और संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शक नियम जारी किए. साथ ही साथ, वित्त मंत्री ने इस बजट में रिजर्व बैंक द्वारा चुने गए भारतीय निजी बैंकों में

विदेशी बैंकों को 74% हिस्सा लेने की इजाजत दी. उन्हें और मालामाल करने के लिए इस बजट ने भविष्य निधि और पेन्शन निधि के क्षेत्रों में एक सुधार (यानी निजीकरण) प्रकिया भी शुरू की. आश्चर्य की बात नहीं, बजट पेश करने के बाद एक हफ्ते के अन्दर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और बड़े निवेश बैंकों ने हमारे देश पर एक बड़े हमले की घोषणा कर दी. 7 मार्च को 'एकॉनमिक टाइम्स' ने यह सुर्खी लगाई कि ''मेर्रिल और गोल्डमैन भारत में बड़ा बैंक–धमाका करेंगे'' और ''वित्तीय सेवाओं में बड़ी नामी–गिरामी कम्पनियों की नजर भारतीय बैंकिंग में जगह पाने पर.'' डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक ऐसा पहला बैंक बनने जा रहा है जिसमें किसी विदेशी प्रमोटर की हिस्सेदारी 49% से ज्यादा हो.

विदेशी सट्टा (संस्थागत) पूंजी (एफआईआई) को करों में भारी–भरकम छूट जारी रहेगी. ज्यादातर तगड़ी वित्तीय कम्पनियों को करों से मुक्त रखा गया. अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा किए गए पैसे पर टैक्स न लगाने की नीति जारी रखने की घोषणा की गई. विदेशी पूंजी को इस प्रकार भारी रियायतें देने से हमारे देश में सट्टा पूंजी का व्यापक बहाव होने में कोई आश्चर्य नहीं है. इसके चलते शेयर बाजारों में सूचकांक कृत्रिम ढंग से अंधाधुंध बढ़ता जा रहा है. बजट के पहले दो हफ्तों में, प्रत्याशा में, सट्टा पूंजी ने देश के शेयर बाजार में अभूतपूर्व रूप से बड़े पैमाने पर (5.5 अरब डॉलर, यानी 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजी) प्रवेश किया. पूरे 2005–06 के खर्च के लिए बजट में बनाई गई केन्द्रीय योजना से 35% ज्यादा है. 2004–05 में हमारे देश में कुल विदेशी सट्टा पूंजी 15.4 अरब डॉलर आई थी – यानी उसके पहले साल के मुकाबले 40% ज्यादा. बजट के बाद विदेशी सट्टा पूंजी का तेज बहाव जारी रहा.

हमारे देश में साम्राज्यवाद की सुनियोजित घुसपैठ का एक और प्रमुख क्षेत्र है अनुसन्धान और विकास. वे यहां उपलब्ध नए पेटेन्ट कानून, सस्ती सुविधाओं और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार का इस्तेमाल करना चाहते हैं. प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और साम्राज्यवादी देश भारत का इस उद्देश्य से इस्तेमाल कर रहे हैं. इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए इस बजट ने बंगलूर स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, जिसका जुड़ाव बदनाम मॉन्सान्टो से है, को 100 करोड़ रुपए तथा दवा कम्पनियों को उनके अनुसंधान व विकास के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए. जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान और उस प्रकार की अन्य योजनाओं के लिए आवंटित मोटी राशियां इस बजट में अलग–अलग मदों में छुपाकर रखी गईं.

बड़े पैमाने पर साम्राज्यवादी घुसपैठ के लिए एक और प्रस्तावित क्षेत्र है फुटकर बाजार जिसे इस बजट ने खोलने का फैसला किया है. बजट के थोड़े पहले निर्माण और रियल एस्टेट को भी विदेशी पूंजीनिवेश के लिए खोलने का फैसला लिया गया था. इसमें कोई आश्चर्य नहीं था क्योंकि आगामी साल शॉपिंग मालों और हाइवे परियोजनाओं में भारी पूंजीनिवेश की योजनाएं चल रही हैं. 2005–06 में 93 माल खुलने वाले हैं. भारत में मालों की योजना में अगले दो सालों में 2,500 करोड़ रुपए और 2010 तक 20,000 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश होने का अनुमान है. जबकि सरकार यह कहती है कि गरीबों के लिए सब्सिडी योजनाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, वहीं उसने 9,320 करोड़ रुपए वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के विशालकाय मद में 33% की बढ़ोत्तरी की. विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 758 करोड़ रुपए के मद में 58% की भारी बढ़ोत्तरी की. इतने सारे पैसे भारतीय पर्यटन पर महज विज्ञापन देने में खर्चे जाएंगे. इनमें ज्यादातर ठेके तो साम्राज्यवादियों से गठजोड़ करने वाली कम्पनियों को मिल जाएंगे.

आखिर पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बजट ने 108 वस्तुओं, जिसमें 30 से ज्यादा होजरी और कपड़ा लाइन की हैं, पर से आरक्षण हटाकर छोटे उद्योगों पर बड़ा हमला किया है. इन क्षेत्रों में बड़े पूंजीपतियों और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया गया. कपड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, को पहले से ही बेरहमी से शोषण किया जा रहा है. इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कुछ ही दिनों में वे कपड़ा उद्योग में मजदूर कानूनों में दो बड़े बदलाव करने वाले हैं. मौजूदा 60 घण्टे प्रति सप्ताह वाले कार्य सप्ताह को बढ़ाना और महिलाओं को रात पाली में रखने पर प्रतिबन्ध हटाना इसमें शामिल हैं. मजे की बात यह है कि 'वामपंथी' भाकपा और माकपा ने इनमें से किसी एक भी कदम का विरोध नहीं किया !!!

ये सभी छूटें और रियायतें बड़े पूंजीपतियों को तोहफे में दी गईं जबकि उनके हित में आर्थिक नीतियों में किए गए बदलावों की बदौलत वे पिछले कई सालों से लगातार भारी–भरकम मुनाफे कमा ही रहे थे. 'एकॉनमिक टाइम्स' के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 2,500 शीर्ष कम्पनियों के मुनाफे 2002 में 64%, 2003 में 62% और 2004 में 36 प्रतिशत बढ़े थे. जबकि बिक्री में पर्याप्त बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, ऐसे में मुनाफों में इतनी भारी बढ़ोत्तरी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी. सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर दी गई रियायतों और मजदूर वर्ग के शोषण में बड़े पैमाने पर की गई बढ़ोत्तरी से ही यह सब सम्भव हो पाया. वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने न सिफ कपड़ा उद्योग में श्रम कानूनों में बदलाव करने की योजना बनाई, बल्कि 'हायर एण्ड फायर' (यानी काम पर रखो और निकाल दो) नीति पेश करते हुए औद्योगिक विवादों के कानून को भी पूरी तरह से बदल देगी. इस तरह, इन सारे तोहफों और कड़े श्रम कानूनों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और दलाल पूंजीपतियों को और ज्यादा भारी मुनाफे मिल जाएंगे. क्या देश की जनता को, जिसकी मुसीबतें आए दिन बढ़ रही हैं, इसे सह लेना चाहिए?

फासीवाद को बढ़ावा देने वाला बजट

संसद के बजट सत्र का उद्घाटन–भाषण देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा 'वामपंथी उग्रवाद' से है. दरअसल गृह मंत्रालय, पुलिस अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों के लिए अब यह एक नया राग बन गया है. अब सिर्फ आइएसआइ, कश्मीर और मुस्लिम आतंकवादियों का ही खौफ नहीं है. दरअसल इस तथाकथित 'वामपंथी उग्रवाद' शासक वर्गों की मौजूदा नीतियों के खिलाफ जनता में बढ़ते असन्तोष का अत्यन्त जुझारू और परिणामशील ध्रुव के सिवाए कुछ भी नहीं है. यह बजट बढ़ते फासीवाद की नीतियों को ज्यादा नुकीले दांत प्रदान करता है

ताकि जनता में बढ़ते असन्तोष को दबाया जा सके.

यह दो तरीकों में प्रतिबिम्बित हो रहा है : पहला, सेना और पुलिस के खर्च में भारी–भरकम बढ़ोत्तरी और दूसरा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वंचित करते हुए वित्तीय संसाधनों का ज्यादा केन्द्रीकरण. दोनों पर नजर डाली जाए.

जहां तक सेना और पुलिस का सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कभी पैसों की कमी पड़ी हो. रक्षा खर्च जो कि पिछले साल 77,000 करोड़ रुपए रहा, को इस वर्ष 8% बढ़ाकर 84,000 करोड़ रुपए कर दिया गया. अगर इसमें उन ढेर सारे गुप्त खर्चों को जोड़ लिया जाए, जिन्हें पेन्शन, सेना/अन्तरिक्ष अनुसन्धान, खुफिया विभाग, अर्ध–सैनिक बलों, आदि पर बहाया जाता है, तो यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए से भी पार हो जाता है. सैन्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा विद्रोह–विरोधी कार्यवाहियों पर किया जाता है, यानी देश की जनता का दमन करने के लिए. सैन्य खरीदियों पर आवंटित राशि में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी की गई है. पिछले साल इस मद में 33,472 करोड़ रुपए खर्चे गए थे, जबकि इस साल वित्त मंत्री ने सैन्य साजोसामान खरीदने के लिए 34,472 करोड़ रुपए आवन्टित किए. इसकी तुलना ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आबन्टित राशि से की जाए जिसमें सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए ही आवन्टित हैं ! इसके अलावा केन्द्रीय पुलिस बलों पर खर्च पिछले साल के 10,756 करोड़ रुपए से 12,552 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया. इसके अतिरिक्त 1,250 करोड़ रुपए अलग से आधुनिकीकरण पर रखा गया. पूर्वोत्तर इलाके में विद्रोह–विरोधी कार्यवाहियों के लिए और 450 करोड़ रुपए तथा सड़क निर्माण के लिए 9,308 करोड़ रुपए का आवन्टन किया गया. इसका एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार द्वारा संचालित कम तीव्रता वाला संघर्ष की योजनाओं में चला जाएगा.

इस बजट में एक बड़ा हमला किया गया है राज्यों की संसाधनों को विकसित करने की क्षमता पर. चूंकि अधिकांश कल्याण योजनाएं राज्यों के हाथों चलाई जाती हैं, इसलिए विभिन्न राज्यों की गरीब जनता पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा. इसके अलावा एक विशाल संघीय ढांचा होने से तानाशाही बढ़ती है. वैट (मूल्य संवर्धन कर) कानून को लागू करने से राज्यों के अपने संसाधनों को बढ़ाने के अधिकारों पर गंभीर आघात होगा. इसके अलावा भी राज्यों के वित्तीय अधिकारों को दबाने के कई कदम उठाए गए हैं इस बजट में.

जनोन्मुखी कर नीति की दरकार

चिदम्बरम का यह कहना कि काले धन को कम करने के लिए ही उन्होंने बैंक से निकाले जाने वाले हर 10 हजार रुपए पर 10 रुपए का कर लगाया है, बकवास है. यह मध्यम वर्गों की जनता को प्रताड़ित करने का एक नायाब तरीका है. इससे राज्य मशीनरी मध्यम वर्ग के लोगों की एक–एक वित्तीय गतिविधि पर नजर रख सकती है. काला धन, जोकि पूरी अर्थव्यवस्था का 40% है, 10–10 हजार रुपयों में नहीं, बल्कि करोड़ों में होता है. यह कदम जितना मध्यम वर्ग के विरोध में है, उतना ही बड़े पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों, उच्च नौकरशाहों के पक्ष में है.

चिदम्बरम का अपना जमात – यानी राजनीतिकों पर इस कर का कोई असर नहीं पड़ने वाला. यह प्रताड़नापूर्ण टैक्स न सिर्फ पैसे निकालने पर लागू होगा, बल्कि फिक्सेड डिपाजिट्स, ट्रैवेलर्स चेक्स आदि तमाम नकदी लेनदेनों पर लागू होगा. मजे की बात यह है कि आज देश में ऐसे सिर्फ 1 लाख लोग हैं जो 10 लाख रुपये से ज्यादा आय कमाते हुए टैक्स भर रहे हैं, जबकि ऐसे महज 10 लाख लोग मौजूद हैं जो सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा आय कमाते हुए टैक्स भरते हैं. सुजित भल्ला के अध्ययन के मुताबिक 3 से 10 लाख रुपए के बीच कमाने वाले लोग 55 लाख से ज्यादा हैं. इस वर्ग पर टैक्स जरूर लगना चाहिए. आज सम्पन्न लोगों के खर्चों पर नजर डालने से लगता है सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले (तमाम राजनीतिकों को मिलाकर) लोग 10 लाख से ज्यादा होंगे. कर राजस्व बढ़ाने के लिए और करों का दायरा बढ़ाने के लिए इस वर्ग का नजरअन्दाज क्यों किया जा रहा है? मध्यम वर्ग को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

इसका जवाब लगातार सरकारों द्वारा लागू विकास नीतियों में निहित है जिन्हें कि साम्राज्यवादियों ने प्रायोजित किया है. शासक चाहते हैं कि देश के गरीब और मध्यम वर्गों से ज्यादा से ज्यादा निचोड़ा जाए और रईस लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए. औद्योगिक विकास और बाजार का विस्तार आबादी की सामान्य क्रय शक्ति को बढ़ाकर नहीं, बल्कि टॉप 5%, खासकर टॉप 1% लोगों का पैसा बढ़ाकर हासिल किए गए. इसके अलावा साम्राज्यवादियों के हितों का पोषण करते हुए निर्यात बाजारों को विकसित कर इन्हें हासिल किया गया. सरकारों का यह टिकाऊ रुख कभी नहीं रहा कि सम्पन्न लोगों पर टैक्स बढ़ाकर संसाधनों को विकसित किया जाए. इसके उलटे उन्हें एक के बाद एक रियायत देने की नीति रही है ताकि वे और ज्यादा खर्च कर सकें. सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि गरीब और मध्यम वर्गों पर टैक्स बढ़ाकर कर राजस्व बढ़ाया जाए और करों के दायरे को फैलाया जाए.

किसी भी समतामूलक समाज में नीति इसके बिलकुल उलटी होगी. करों में रियायतें और राहतें गरीबों और मध्यम वगों को दी जातीं. रईस लोगों और व्यापार के मुनाफों पर भारी कर लगाया जाता. इससे विकास की समूची प्रक्रिया पर सकारात्मक असर पड़ेगा. आम लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी. औद्योगिक विकास के मामले में मुख्य जोर जरूरती चीजों पर रहा करता न कि विलासिता की चीजों पर. रईस लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाता और विलासिता की चीजों की उपलब्धता कम कर दी जाती. बढ़ी हुई क्रय शक्ति से औद्योगिक उत्पादन में एक जबर्दस्त उछाल आ जाती. कैपिटल और उत्पादक सामग्रियों में इजाफा आ जाता.

एक सच्चे स्वाधीन देश में विकास का तरीका यही होना चाहिए. लेकिन सत्ता पर विराजमान ताकतवर रईस वर्ग इसकी इजाजत नहीं देती. विकास के इस नमूने को लागू करने की किसी भी कोशिश को वह विनाशकारी करार देगा. ऐसी किसी भी पहल को वे आतंकवाद और अराजकतावाद कहकर दबा देंगे. 'स्थिरता' को बनाए रखने के लिए पुलिस व सेना भेजी जाएंगी. तो ऐसे में जनता के पास क्या जवाब होगा, सिवाए क्रान्ति करने के. ✶

वक्तव्य

क्रान्तिकारी संगठनों पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध

लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला !

19 अप्रैल 2005 को छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के "गैर-कानूनी गतिविधियों के निरोधक अधिनियम" के तहत क्रान्तिकारी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। प्रतिबन्धित संगठनों में 'दण्डकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ (डीएकेएमएस)', 'क्रान्तिकारी आदिवासी महिला संगठन (केएएमएस)' और 'स्थानीय छापामार दस्ता (एलजीएस)' शामिल हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के मार्गदर्शन में काम करने वाले इन तीन संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाकर, क्रान्तिकारी आन्दोलन पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी बर्बरतापूर्ण दमन को वैधता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। वास्तव में अविभाजित मध्यप्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के दिनों से ही हमारी पार्टी और अन्य जन संगठनों पर प्रतिबन्ध की बात चल रही थी। लेकिन चूंकि लुटेरे शासक वर्गों की कुटिल नीति यह भी रही कि प्रतिबन्ध लगाए बिना ही दमन के सारे हथकण्डे अपनाए जाएं, इसलिए प्रतिबन्ध की पेशकश को अब तक अमली रूप नहीं मिला था।

छत्तीसगढ़ में जबसे रमन सिंह की अगुवाई में भाजपा सरकार का गठन हुआ, तब से क्रान्तिकारी आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से पुलिसिया दमन में तेजी लाई गई है। हालांकि अभी तक घोषित रूप से तो प्रतिबन्ध नहीं था, पर जहां भी किसी संगठन का सदस्य मिला या फिर किसी व्यक्ति पर संगठन सदस्य होने का शक हुआ, तो उसे बाकायदा मारा-पीटा जा रहा है, झूठे केसों में जेल भेजा जा रहा है या फिर झूठी मुठभेड़ों में उसकी हत्या की जा रही है। हमारे संगठनों पर प्रतिबन्ध नहीं था तो हमें खुले तौर पर, जनवादी तरीके से कोई कार्यक्रम आयोजित करने की छूट दी गई हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब तक के इतिहास पर नजर डाली जाए तो साफ पता चलता है कि जहां भी लोगों ने जनतांत्रिक ढंग से कोई सभा, रैली या प्रदर्शन करने का फैसला लिया वहां सरकार ने पुलिस बलों के जरिए आतंक मचाकर उन्हें भंग ही कर दिया। पिछले 8 मार्च को सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में एक महिला संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभा करने की कोशिश की तो पुलिस बलों ने उसे यह कहकर भंग कर दिया कि उस संगठन के साथ नक्सलियों का सम्बन्ध है। वहां पर बड़ी संख्या में उक्त संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। पिछले साल अक्टूबर में बस्तर जिले के नारायणपुर शहर में भी लोगों ने 'महिला संघर्ष समिति' के नेतृत्व में एक रैली निकालने की कोशिश की तो सरकार ने पहले ही धारा 144 लागू करके इस संगठन के कई पदाधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाकर गिरफ्तार किया। हाल ही में नारायणपुर क्षेत्र के लोगों ने नए पुलिस थाने की स्थापना के खिलाफ रैली निकालने का फैसला किया तो सरकार ने एक सप्ताह पहले ही फिर एक बार धारा 144 लागू कर दिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि सरकार विरोध के स्वरों को किसी भी कीमत पर दबाने पर तुली हुई है।

जहां तक क्रान्तिकारी संगठनों और उनकी गतिविधियों का सवाल है, प्रतिबन्ध की यह घोषणा महज औपचारिकता ही कही जा सकती है। अब इस प्रतिबन्ध की आड़ में सरकार लोगों पर और ज्यादा भयानक दमन चलाने की कोशिश करेगी। इसके सहारे आम लोगों और समर्थकों पर और ज्यादा कहर बरपाने की कोशिश करेगी। इस प्रतिबन्ध से किसी भी व्यक्ति को प्रतिबन्धित संगठन का सदस्य बताकर जेलों में डालने या मार डालने के मनमाने अधिकार सरकार को मिल जाते हैं।

इसके पहले आन्ध्रप्रदेश सरकार ने हमारी पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया था। बाद में राजग की केन्द्र सरकार ने पोटा कानून के तहत हमारी पार्टी पर प्रतिबन्ध लगाया था जो अब पोटा की समाप्ति के बाद यूएपीए के तहत जारी है। बिहार सरकार का भी क्रान्तिकारी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का इतिहास रहा है। उपनिवेशी शासन काल में अंग्रेजों ने भी कई संघर्षशील संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया था। अब दुनिया का नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद भी वही काम कर रहा है और करवा रहा है। पर सचाई यह है कि जब तक इस दुनिया में शोषण, उत्पीड़न, असमानता, भूख, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, भेदभाव, महंगाई आदि समस्याएं होंगी तब तक इनके खिलाफ जनता संघर्ष करती ही रहेगी। दमन और प्रतिबन्ध के जरिए जनता के संघर्षों को हमेशा के लिए कुचल देना सम्भव नहीं है, इतिहास ही इसका गवाह है।

प्यारे लोगो, बुद्धिजीवियो, पत्रकारो, मजदूरो, किसानो, छात्रो, नौजवानो !

अब तक "नक्सलियों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं" की रट लगाते रहने वाली रमन सरकार अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। क्रान्तिकारी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने का उसका यह फैसला देश के संवैधानिक मूल्यों पर ही कुठाराघात है। हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि इस प्रतिबन्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं - सरकार से मांग करें कि वह इस प्रतिबन्ध को वापस ले। आपसे हमारा आग्रह है दण्डकारण्य की जनता पर, क्रान्तिकारी संगठनों पर केन्द्र की यूपीए सरकार की देखरेख में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों द्वारा जारी पाशविक पुलिसिया दमन की निंदा करें।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ,

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

22 अप्रैल 2005

भाकपा (माओवादी)

वक्तव्य

कांग्रेसी नेताओं की दिवालिया राजनीति का पर्दाफाश करो !
बस्तर में जारी सरकारी दमन का विरोध करो !!

प्यारे लोगो,

कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक दल नेता महेन्द्र कर्मा, कवासी लखमा और राजेन्द्र पामभोई ने बस्तर के कुछ इलाकों का दौरा किया. इनका उद्देश्य यह बताया गया था कि वे नक्सली समस्या के बढ़ने के कारणों का पता लगाएंगे और सरकार को आवश्यक सुझाव देंगे. इन नेताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि हालात काफी गंभीर है और यहां तैनात पुलिस व अर्ध सैनिक बलों का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है. विपक्ष के नेता होने के नाते इन लोगों ने जनता पर सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों व जुल्मों पर एक शब्द भी नहीं कहा. रमन सरकार की दमनकारी नीतियों पर इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं है. इससे उनका इशारा साफ है. वे चाहते हैं कि पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के जरिए दमन और बढ़ाया जाए. इसके कुछ माह पहले मर्री शशिधर रेड्डी की अगुवाई में कांग्रेस का एक टास्क फोर्स दल ने भी बस्तर का दौरा किया था. काग्रेस हमेशा यह दिखावा करती रही कि वह नक्सलवाद को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से देखती है. लेकिन बस्तर की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि इनके नेता महेन्द्र कर्मा का इतिहास क्या है. कर्मा पहले से ही बस्तर जनता के न्यूयपूर्ण आन्दोलन का विरोधी रहा है. उन्होंने 'जन जागरण अभियान' के नाम से दो-तीन बार जनता के खिलाफ एक व्यापक दमन अभियान चलाया था, जिसकी यादें जनता के जेहन में अभी भी ताजी हैं. उस अभियान के दौरान कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था और लोगों को मारा-पीटा गया था. कर्मा, लखमा और पामभोई के बयानों से अब उनकी यह मंशा साफ हो चुकी है कि वे इस आन्दोलन को रमन सरकार के हाथों और ज्यादा क्रूरता व पाशविकता से कुचलवाना चाहते हैं. दरअसल कांग्रेस-नीत केन्द्र की यूपीए सरकार का दृष्टिकोण भी यही है कि इस आन्दोलन को कठोर तरीकों से कुचल दिया जाए. हमारी पार्टी कर्मा, लखमा और पामभोई के जन-विरोधी व दमनकारी रवैए की कड़ी निंदा करती है और चेतावनी देती है कि बस्तरिया जनता उन्हें अच्छा सबक सिखा देगी.

पिछले कुछ दिनों से अखबारों में बस्तर में पुलिस की कार्यवाहियों को लेकर जो खबरें छप रही हैं, वे सभ्य समाज को झकझोरने वाली हैं. आज पूरे बस्तर में आदिवासी बस्तियां सीआरपीएफ और पुलिस बलों के लौह जूतों तले रौंदी जा रही हैं. समूचा बस्तर एक सैन्य छावनी में बदल गया लग रहा है. दर्जनों लोगों को 'इनामी नक्सली' या 'संघम सदस्य' बताकर गिरफ्तार किया जा रहा है. यहां तक कि 12-13 साल के बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है. उन्हें बुरी तरह पीट-पीटकर बाद में झूठे मामले दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है. सशस्त्र बल जिस किसी भी गांव में धावा बोलते हैं वहां की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार से लेकर बलात्कार तक एक आम बात हो चुकी है. छत्तीसगढ़ में पहले से मौजूद सीआरपीएफ की 7 बटालियनों के अलावा अब गुजरात और मणिपुर से एक-एक बटालियन मंगाई गई है. सैन्य हेलिकॉप्टर, बख्तरबन्द गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार, आदि मंगाए जा रहे हैं. केन्द्र की यूपीए सरकार छग सरकार को मुंह मांगे वरदान दे रही है. सेना के आला अफसर बस्तर का दौरा करके पुलिस व अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं. इन सारी तैयारियों और कवायद को देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार किसी शत्रु देश के खिलाफ युद्ध करने जा रही हो.

दूसरी तरफ सरकार अपने मीडिया के जरिए यह प्रचार कर रही है कि बस्तर में, खासकर अबूझमाड़ में नक्सलवादियों ने हथियार कारखाना खोला है और बंकर बनाए हुए हैं. सरकार यह दुष्प्रचार इसलिए कर रही है ताकि यहां की जनता पर जारी बर्बरतापूर्ण दमन को वैधता हासिल की जा सके. 'आइएसआइ के साथ नक्सलवादियों के सम्बन्ध हैं' वाला प्रचार तो काफी पुराना हो चुका है. समय-समय पर इस बेबुनियाद आरोप को नए सिरे से उछाला जा रहा है. संघर्षशील व विवेकशील जनता को यह अच्छी तरह मालूम है कि सच्चाई क्या है. निष्पक्ष मीडिया कहलाने वाले अखबार भी पुलिस अधिकारी जो बयान देते हैं उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं, सच्चाई को जानने की सचेत कोशिश नहीं कर रहे हैं. आज समूचे दण्डकारण्य में हमारी पार्टी के नेतृत्व में लोग तरह-तरह के विकास कार्यक्रम अपना रहे हैं. जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां कुएं खोद रहे हैं. अपने खेतों की सिंचाई के लिए खुद ही तालाब का निर्माण कर रहे हैं. माड़ जैसे पिछड़े इलाकों के दर्जनों गांवों में हमारे जन संगठनों के नेतृत्व में जनता उन्नत खेती की दिशा में कदम बढ़ा रही है. जहां स्कूल नहीं है वहां 'जनताना सरकार' की अगुवाई में 'जन पाठशाला' का निर्माण किया जा रहा है. आज संघर्ष इलाके के लगभग हर गांव में जो भी आदमी बीमार पड़ता है वह सरकार की तरफ नहीं देख रहा है. वह या तो क्रान्तिकारी जन संगठनों के नेतृत्व में चलने वाले 'लोक स्वास्थ्य केन्द्र' में अपना इलाज कराता है या फिर हमारी पीएलजीए के दस्तों के पास आता है. इन सभी बातों से यही स्पष्ट होता है कि तथाकथित आजादी के बाद 58 सालों में सरकार द्वारा बरती गई लापरवाही को सह चुकी जनता अब अपने भाग्य का फैसला खुद अपने हाथों में ले चुकी है. सरकार इन सब बातों पर परदा डालते हुए इस प्रचार में लगी हुई है कि नक्सलवादी हथियार बना रहे हैं और हिंसात्मक कार्यवाहियां कर रहे हैं.

यह बात सही है कि हमारी पीएलजीए ने पिछले एक-दो महीनों में

बस्तर और गड़चिरोली इलाकों में पुलिस पर, खासकर सीआरपीएफ पर कुछ हमले किए हैं. इन सारे हमलों में हमारे बहादुर लाल योद्धाओं ने अलग-अलग बलों के 20 से अधिक जवानों को मार गिराया और 80 से अधिक लोगों को घायल कर दिया. इस दौरान हमारे चार बहादुर साथी कॉमरेड्स मंगतू (स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य), करुणा (सेक्षन कमाण्डर), विनोद (सेक्षन कमाण्डर) और सोमारी (सदस्या) शहीद हो गए जिनकी मृत्यु 17 मई को धौड़ाई में किए गए हमले के दौरान हुई थी. क्रान्तिकारी आन्दोलन की रक्षा करने तथा पिछले 25 सालों के कठिन संघर्ष के जरिए जनता को हासिल हुई उपलब्धियों को बचाए रखने के लिए ये कार्यवाहियां जरूरी थीं. लेकिन पुलिस हमेशा आम लोगों को मारकर उन्हें नक्सली बताकर अपनी कायरता का नंगा प्रदर्शन कर रही है. लोगों से पैसे लूट रहे हैं. मई के आखिरी सप्ताह में बेलचर के पास जब हमारे पीएलजीए सैनिकों ने एक हमला करके सीआरपीएफ के 5 जवानों को मार गिराया था, तो सीआरपी जवानों ने एक बेकसूर ट्रैक्टर देवनाथ ड्राइवर को गोली मार दी. बाद में उसे नक्सली बताया गया. इसके पहले भी कई अन्य घटनाओं में सीआरपीएफ वालों ने ऐसा ही किया था. अब ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं.

हम छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करते हैं कि बस्तर में पुलिस व अर्ध सैनिक बलों द्वारा चलाए जा रहे बर्बरतापूर्ण दमन की निंदा करें. दण्डकारण्य जनता के न्यायपूर्ण आन्दोलनों का समर्थन करें. देश के पत्रकारों, लेखकों, चित्रकारों, अध्यापकों, छात्रों और अन्य तमाम बुद्धिजीवियों से हमारी अपील है कि दण्डकारण्य में पिछले 25 सालों के संघर्ष की बदौलत जनता ने जो उपलब्धियां हासिल कीं और अपने जीवन में जो बदलाव खुद लाए उन्हें आप खुद आकर देखें. आप खुद अपनी आंखों से देखें कि इस संघर्ष ने उनकी जिन्दगी को कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया. उसके बाद आप खुद तय कर लें कि यह संघर्ष जायज है भी या नहीं .

इस मौके पर हम अपनी पार्टी कतारों, जन मुक्ति सेना के जांबाज कमाण्डरों व बहादुर सैनिकों, जन संगठनों तथा जनता का आह्वान करते हैं कि सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए मुस्तैदी से तैयार रहें और जनता के हितों की हर हालत में रक्षा करने की कोशिश करें. हमारे संघर्ष की उपलब्धियों को छीनकर, इस आन्दोलन का जड़ से सफाया करने की मंशा से संघर्ष इलाकों में घुसने वाले पुलिस, सीएसएफ, सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस, गुजरात पुलिस, टास्क फोर्स, आदि बलों का मुंहतोड़ जवाब दें. अत्याचारियों और बलात्कारियों को खास तौर पर निशाना बनाएं.

(कोसा)

सचिव

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

15 जून 2005

भाकपा (माओवादी)

(..... पेज 19 का शेष)

इन हमलों में खासकर सीआरपीएफ को भारी नुकसान उठाना पड़ा. उसके एक दर्जन से ज्यादा जवान कुत्ते की मौत मारे गए. सीआरपीएफ बस्तर में आतंक का पर्याय बन चुका था. जनता की इन प्रतिरोधी कार्रवाइयों को बहाना बनाकर सरकार ने अपनी दमनात्मक नीतियों में इजाफा किया है. 1 जून को छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अफसरों ने भारतीय सेना के हथियार विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा किया. इससे इनकी सैन्य तैयारियों का अन्दाजा लगाया जा सकता है.

रमन सरकार ने कांकेर में छापामार-विरोधी लड़ाई में पुलिस बलों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का जंगिल वारफेर स्कूल भी खोलने का फैसला लिया है. वह पहले से ही अपने पुलिस बलों को दूसरे राज्यों में, खासकर आन्ध्र भेजकर प्रशिक्षण दिलवा रही है. चूंकि वर्तमान क्रान्तिकारी संघर्ष एक दीर्घकालिक संघर्ष है, इसे अच्छी तरह समझकर सरकार भी दीर्घकालिक तैयारियां कर रही है.

एक तरफ दमन की कार्यवाहियों को अंजाम देते हुए ही सरकार दुष्प्रचार को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. हाल ही में उत्तर बस्तर के कुछ इलाकों में 'बस्तर मित्र' के नाम पर और माड़ क्षेत्र में 'बस्तर संघर्ष समिति' के नाम पर पुलिस वालों ने पर्चे बांटे हैं. उन पर्चों में पार्टी व पीएलजीए के खिलाफ बेबुनियाद आरोप और अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं. ध्यान रहे कि बस्तर संघर्ष समिति एक ऐसा जन संगठन है जिसने पृथक बस्तर राज्य की मांग से कई बार रैलियां निकालीं और अन्य संघर्ष चलाए. ऐसे एक जनवादी जन संगठन के नाम का दुरुपयोग करने की इस पुलिसिया हरकत की कितनी निंदा की जाए कम है. राजनीतिक स्तर पर हमारा मुकाबला करने में अक्षम सरकारी व पुलिस अधिकारी इस तरह छद्म संगठनों के नाम से नीचतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं.

दण्डकारण्य की जनता ने पिछले 25 बरसों से संघर्ष करते हुए अनेक उपलब्धियां हासिल कीं. लुटेरी राजसत्ता को धता बताकर गांव-गांव में वह खुद की सरकार, यानी जनताना सरकार की स्थापना कर रही है. दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने के इरादे जारी इस लड़ाई में जनता कई कुरबानियां दे रही है. तथाकथित आजादी के 58 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इस लुटेरी सरकार ने यहां के आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया. उनके खेतों के लिए पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, डाक्टर नहीं है, न स्कूल है, न गुरूजी. इस स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ही यह जन संघर्ष चल रहा है. दरअसल इस स्थिति के लिए लुटेरी व्यवस्था जिम्मेदार है. इस व्यवस्था को जड़ से बदले बिना परिवर्तन सम्भव नहीं है. इसी दृष्टिकोण से यह लड़ाई चल रही है. इस जायज संघर्ष पर लुटेरी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक दमन की हर तरफ निंदा करने की जरूरत है. दमन प्रतिरोध को ही जन्म देता है. निश्चित रूप से दण्डकारण्य की जनता और उनकी अगुवाई कर रही जन मुक्ति छापामार सेना इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगी और परास्त करेंगी. ✶

पुलिसिया दमन और सरकारी सुधार कार्यक्रम – दोनों का साझा लक्ष्य क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया ही

दमन और सुधार दोनों को ठुकराकर संघर्ष को आगे बढ़ाओ

दण्डकारण्य की जनता पिछले कुछ सालों से दमन और सुधार दोनों को झेलती आ रही है. दमन का मतलब कोई भी समझ सकता है, यानी पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियां, यातनाएं, अत्याचार, बलात्कार, घरों को जलाना, सम्पत्तियों को नष्ट करना, लापता कर देना, झूठी मुठभेड़ों में किसानों की हत्या करना, इत्यादि. और सुधारों का मतलब आम तौर पर वित्तीय या नकदी सुधार कार्यक्रम हैं. किसानों को कर्ज के नाम से नकद राशि देना, खेती की जरूरतों और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों के नाम पर ऋण देना, लोगों की साझा जरूरतों के लिए काम चलाना, लोगों को व्यक्तिगत सहायता, आदि बहुत सारे शामिल हैं. ये गांव, विकासखण्ड, तहसील और जिला स्तर पर चलाए जाते हैं. इन्हें केन्द्र व राज्य सरकारें जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर चलाती रहती हैं. इसके अलावा आदिवासियों के विकास के नाम पर चलाई जाने वाली योजनाएं भी कई सारी हैं. इन योजनाओं के तहत किसानों को कुछ फायदे मुफ्त में ही मिल जाते हैं. और अधिकांश चीजों पर भारी–भरकम रियायतें दी जाती हैं. इनके बारे में किसान अच्छी तरह जानते हैं. लेकिन दमन और सुधार के बीच के सम्बन्ध और अन्तर को राजनीतिक रूप से समझने की जरूरत ज्यादा है. इन दोनों के प्रति क्या रुख अपनाया जाए, इस पर स्पष्टता न होने से क्रान्तिकारी आन्दोलन को नुकसान पहुंच सकता है.

जबसे दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तार हुआ, तभी से यह दमन का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहा है. सरकारें शुरू से ही यहां दमन करते आ रही हैं ताकि क्रान्तिकारी आन्दोलन टिक न सके. सरकारों को यह डर था कि अगर इस विशाल जंगली इलाके में यह आन्दोलन जम जाए तो उनके लुटेरे शासन को आंच आ सकती है. शुरू में ही, 2 नवम्बर 1980 को महाराष्ट्र पुलिस ने कॉमरेड पेद्दि शंकर की हत्या की. सरकार ने एक तरफ मुठभेड़ों और गिरफ्तारियों को अंजाम देते हुए दूसरी तरफ क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ व्यापक पैमाने पर दुष्प्रचार की मुहिम छेड़ दी. इसके साथ ही साथ सरकारों ने कुछ सुधार कार्यक्रम भी शुरू कर दिए. शुरू में कुछ किसानों को वित्तीय सहायता देने पर जोर दिया गया था. बाद में ज्यों–ज्यों क्रान्तिकारी आन्दोलन मजबूत होता गया, त्यों–त्यों सुधारों में तेजी लाई गई.

आम तौर पर सरकारें क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करने के लिए दमन का ही सहारा ले रही हैं. पर इन दमनकारी नीतियों को बाहरी जनता देख व पहचान न सके, इसके लिए राहत व सुधार कार्यक्रम भी कर रही हैं. बेहद गरीबी से दो–चार किसानों के दिल में सरकार के प्रति अच्छी छवि बन जाए, यह भी सुधारों का एक उद्देश्य है. ग्रामीण इलाकों में धनी किसानों और मुखियाओं के एक तबके को इन सुधारों के जरिए फायदा पहुंचाना और उनसे मदद लेते हुए संघर्ष का दमन करना भी सरकार की मंशा है. दमन को वैधता हासिल करने के लिए भी सरकार सुधार कार्यक्रमों को अंजाम देती है. पिछले 25 सालों से ऐसे लोगों की एक जमात बढ़ चुकी है जिनका तर्क है कि नक्सलवाद या क्रान्तिकारी आन्दोलन कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं में हैं. इनकी मांग यह है कि संघर्ष के इलाकों में 'विकास' कार्यक्रम चलाए जाएं. इनमें कुछ प्रगतिशील लोग भी हैं, कुछ का ताल्लुक नौकरशाही से भी है. कुछ लोग सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि समस्या के समाधान के लिए सरकार नक्सलवादियों के साथ शांति वार्ता करे. ऐसे लोगों की कमजोरी यह है कि वे इस बात को समझने में विफल हो रहे हैं कि लुटेरे शासक वर्ग इस प्रकार के कुछेक 'विकास' कार्यक्रमों को अंजाम देकर शोषण और उत्पीड़न को हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं. वे यह भी नहीं समझ रहे हैं कि क्रान्तिकारी आन्दोलन का लक्ष्य कुछेक जन समस्याओं का निराकरण करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से बदलकर मजदूर–किसान की एकता की बुनियाद पर एक नई जनवादी व्यवस्था को कायम करना है.

क्रान्तिकारी संगठन दण्डकारण्य में सरकार के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं. सरकार अपने मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर यह कहते हुए दुष्प्रचार कर रही है कि 'नक्सलवादी विकास के विरोधी हैं'. इस दुष्प्रचार अभियान से भ्रमित होकर बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग का एक हिस्सा इसे सच मानने लगा है. खासकर उन लोगों पर इस दुष्प्रचार का असर ज्यादा है जो संघर्ष के इलाकों से बाहर हैं. 'झूठ को सौ बार दोहराने से वह एक दिन सच होकर रह जाएगा' – गोबेल्स के इस कथन का अच्छी तरह पालन करने वाली सरकारें क्रान्तिकारी संगठनों के खिलाफ लगातार जहर उगल रही हैं.

दण्डकारण्य आपार जल, खनिज व वन सम्पदाओं की धरती है. केन्द्र व राज्य सरकारें साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित लुटेरी नीतियों पर चलते हुए यहां पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए आवश्यक आधारिक ढांचा तैयार कर रही हैं. सहज ही सरकारें यहां ऐसी सुधार योजनाएं लागू कर रही हैं जिनसे उनके लुटेरे हितों को भी साधा जा सके. सड़क निर्माण जैसी योजनाओं के दोहरे लक्ष्य है – एक तो पुलिस व अर्द्ध–सैनिक बलों को संघर्ष इलाकों में तेजी से पहुंचाने के लिए सुविधाएं तैयार करना, दूसरा, साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां के संसाधनों को लूटकर ले जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना. आज दण्डकारण्य में पल–फूल रही जनता की जनवादी राजसत्ता के अंगों ने अपने विकास कार्यक्रम खुद ही शुरू किए हैं. सिंचाई, पेयजल, खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रों में विकास काम जारी हैं. अब एक तरफ जनयुद्ध को तेज करते हुए, दूसरी तरफ इन जनोन्मुखी विकास कार्यों में तेजी लानी है. इस लुटेरी व्यवस्था द्वारा जारी हर किस्म के सुधार कार्यक्रम का विरोध करना जरूरी है – नई जनवादी राजसत्ता की स्थापना के लिए यह बहुत जरूरी है. ★

राजकीय दमन

दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने की सरकार की साजिश

21 सितम्बर 2004 को सम्पन्न भाकपा (मा-ले) (पीपुल्सवार) और एमसीसीआई का विलय और नई पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उदय के बाद देश भर में उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई. वहीं शासक वर्गों और उनके साम्राज्यवादी आकाओं की रीढ़ में कंपकंपी पैदा हुई. केन्द्र व राज्य सरकारें यह सोचते हुए कि अगर क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया नहीं किया गया तो लुटेरों की सत्ता को चोट पहुंच सकती है, युद्ध की तैयारियों में तेजी ला रही हैं. सेना के सर्वोच्च अधिकारी ने हाल ही में कहा, ''देश में माओवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, अतः इससे देश की आन्तरिक सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है. यह चिन्ता का विषय है. इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हम पूरी मदद करेंगे.'' इसका मतलब यह है कि सरकार अर्द्ध सैनिक बलों के बाद अब सेना को भी उतारने की तैयारियां कर रही है. 17 जून को हैदराबाद में केन्द्रीय गृहमंत्री की अगुवाई में सम्पन्न 13 राज्यों के पुलिस व सरकारी अधिकारियों की बैठक में संयुक्त टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया गया. सभी प्रभावित राज्यों के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान करने का भी पुख्ता फैसला लिया गया. अब तक नक्सलवादी आन्दोलन को सामाजिक व आर्थिक मसला कहकर डींग मारने वाली यूपीए सरकार के चेहरे से अब नकाब पूरी तरह से उठ चुका है. वह बन्दूक के बल पर ही इस आन्दोलन को कुचलने की तैयारियां तेज कर रही है. यूपीए सरकार सभी राज्य सरकारों को मुंह मांगे अत्याधुनिक हथियार, पैसा, अतिरिक्त बल, आदि मुहैया करवा रही है. यानी इनके बीच सत्ता को लेकर कुत्ता-घसीटी चाहे जितनी भी चलती हो, पर क्रान्तिकारी संघर्ष का दमन करने में इनके बीच मजबूत एकता कायम है. ऐसा इसलिए क्योंकि सारी संसदीय पार्टियां लुटेरों की पार्टियां ही हैं और इस संघर्ष से उन्हीं लुटेरों को खतरा है.

हाल ही में कोलकाता में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड शोम सहित चार अन्य नेताओं को गिरफ्तार करना हमारे इस आन्दोलन पर जारी देश व्यापी हमले का हिस्सा है. खासकर नेतृत्वकारी कॉमरेडों को गिरफ्तार कर और उनकी हत्या कर इस आन्दोलन को तथा देश के अवाम को नेतृत्वविहीन करने की साजिश है यह. पश्चिम बंगाल की तथाकथित 'मार्क्सवादी' सरकार इस नीचतापूर्ण हरकत को अंजाम देकर देशवासियों के सामने साफ तौर पर नंगी हो चुकी है.

दण्डकारण्य के गड़चिरोली डिवीजन में आन्दोलन का सफाया करने के लिए महाराष्ट्र सरकार कमाण्डो बलों को उतारकर लगातार भारी दमनचक्र चला रही है. इधर बस्तर इलाके में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार राज्य पुलिस बलों के अलावा अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दमनात्मक कार्यवाहियां कर रही है. छत्तीसगढ़ में अब तक सीआरपीएफ की 7 बटालियनें मौजूद हैं जिनमें से 5 बस्तर क्षेत्र में तैनात हैं. इसके अलावा अभी-अभी सरकार ने गुजरात और मणिपुर से एक-एक बटालियन मंगाई है. केन्द्र ने राज्य सरकार को इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने की इजाजत पहले ही दे रखी है. खासकर आदिवासी युवाओं को भर्ती करके इन बटालियनों की स्थापना की जा रही है ताकि आदिवासियों के आन्दोलन का दमन खुद उन्हीं की संतानों से करवाया जा सके. दोनों राज्यों की सरकारें तालमेल के साथ गांवों पर छापेमारियां करवा रही हैं. लोगों को गिरफ्तार करना, क्रूर यातनाएं देना आम बात हो गया. छापामार दस्तों का सफाया करने के लिए जंगलों में गश्त व तलाशी अभियान चलाना, जंगलों में जो भी आदमी दिखाई देता उसे इनामी नक्सली बताकर गिरफ्तार करना लगातार जारी है.

छत्तीसगढ़ की रमन सरकार जनता को गुमराह करने के लिए एक तरफ नक्सलवादियों के साथ बातचीत करने की रट लगाते हुए दूसरी तरफ युद्ध की कार्यवाहियों में तेजी ला रही है. विकास कार्यक्रमों के नाम पर वह करोड़ों रुपए बहा रही है. मुख्य रूप से सड़कों और पुलिस थानों व चौकियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. सरकार माओवादियों के खिलाफ पुलिस जवानों को उकसाने के लिए उन्हें मारे जाने या घायल होने पर लाखों का मुआवजा देने का लालच दे रही है. माओवादी छापामारों पर हवाई हमले करने के इरादे से रमन सरकार ने केन्द्र सरकार से हेलिकॉप्टरों की मांग की है. केन्द्र ने तुरन्त ही 4 हेलिकॉप्टर दे दिए. छापामार दस्तों के हमलों से बचने के नाम पर 13 बारूदीसुरंग-रोधक वाहन भी मंगाए गए हैं. ये सब जनता और जन आन्दोलन पर और ज्यादा दमन चलाने के लिए ही किया जा रहा है. जनता के तमाम जनवादी अधिकारों पर हमले करते हुए सरकार ने तीन क्रान्तिकारी संगठनों पर प्रतिबन्ध भी लगा दिया.

छत्तीसगढ़ में ज्यों ही रमन सिंह सरकार का गठन हुआ, उसके तुरन्त बाद नक्सली इलाकों के लिए एसआईबी (स्पेशल इंटलिजेन्स ब्यूरो) का गठन की घोषणा की गई. इसके तहत अन्दरूनी इलाकों में तरह-तरह के नामों से गोपनीय ढंग से जासूसों को भेजने का सिलसिला लगातार जारी है. पुलिस अधिकारी कई लोगों को पागल के भेष में भेजकर उनके जरिए खुफिया सूचना इकट्ठी कर रहे हैं. वे अन्दरूनी गांवों और दूरस्थ जंगलों में घूमकर छापामारों के कैम्पों व अन्य कार्यक्रमों की सूचना इकट्ठी करके अपने अधिकारियों को देने की कोशिश करते हैं. इन्हें लालच में फंसाने के लिए पुलिस अधिकारी ढेरों पैसा दे रहे हैं. ऐसे कुछ लोगों को पीएलजीए सैनिकों ने जनता की मदद से गिरफ्तार करके दण्डित किया है.

जनता और जन संगठनों पर लगातार बढ़ रहे हमलों का मुकाबला करने तथा जनता द्वारा हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने के इरादे से पीएलजीए ने पिछले कुछ महीनों में दण्डकारण्य में कई हमले किए.

(शेष पेज 17 पर ....)

लुटेरे वर्गों के भाड़े के सैनिकों पर पीएलजीए के शानदार हमले

क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ देश भर में जारी चौतरफा हमले के जवाब में उत्पीड़ित जनता की सेना – जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) ने देश के कई हिस्सों में पिछले फरवरी से जवाबी हमलों का एक सिलसिला छेड़ दिया. इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि पुलिस व अर्द्ध–सैन्य बलों के श्वेत आतंक को खत्म कर जनता द्वारा हासिल उपलब्धियों को बचाना, संघर्ष के इलाकों में उठ खड़ी हो रही जनता की राजनीतिक हुकूमत का बचाव करना और उसके विकास में मदद करना. दुश्मन के हथियार छीनकर जनता और जन मुक्ति छापामार सेना को मजबूत बनाना भी इस अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. इस सिलसिले में दण्डकारण्य के अलावा गोंदिया–बालाघाट डिवीजन, उत्तर छत्तीसगढ़, आन्ध्र, बिहार, झारखण्ड, एओबी, आदि इलाकों में कई हमले हुए हैं. पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने दर्जनों पुलिस बलों को मौत के घाट उतार दिया और बीसियों को घायल कर दिया. हालांकि पीएलजीए को भी कुछ नुकसान उठाने पड़े हैं. 17 मई को डौला पुलिस कैम्प पर किए गए हमले में दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड मंगतू समेत चार कॉमरेड शहीद हो गए. पेश है इन प्रतिरोधी कार्यवाहियों का एक संक्षिप्त लेखा–जोखा.

दोडराज एम्बुश में 8 जवानों का सफाया और 11 घायल

22 फरवरी 2005 को गड़चिरोली डिवीजन के भामरागड़ तहसील के दोडराज गांव के पास पीएलजीए की चार सदस्यों की टुकड़ी ने पुलिस पर घात लगाकर हमला किया. बारूदी सुरंग के विस्फोट से किए गए इस हमले में एक थानेदार समेत 8 पुलिस वाले मारे गए और 11 घायल हो गए. गड़चिरोली जिले के अन्दर जनता पर पुलिसिया आतंक जोरों पर है. मारपीट, बलात्कार, जेल में ठूंस देना, बुरी यातनाएं देना, आदि अत्याचारों की कोई गिनती नहीं है. पिछले एक साल के अन्दर गड़चिरोली डिवीजन में पुलिस ने अलग–अलग हमलों में कॉमरेड्स भूमन्ना, पूसू और सरिता की हत्या की थी. दोडराज एम्बुश के जरिए उन तमाम शहीदों का बदला ले लिया गया. खासकर भामरागड़ थानेदार झारकर और हवलदार श्यामराव के इस हमले में कुत्ते की मौत मारे जाने से लोग इतने खुश हो गए कि जगह–जगह त्यौहार मनाए गए क्योंकि उन्हें क्रूरता का पर्याय माना जाता था.

जन मिलिशिया ने दो एसएलआर छीने

मार्च के आखिरी सप्ताह में दन्तेवाड़ा शहर में राज्यपाल का दौरा था. उस समय हेलिपैड की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को जन मिलिशिया ने अपना निशाना बनाया. वहां दुश्मन की कमजोरी का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद जन मिलिशिया की ऐक्शन टीम ने वहां पर मौजूद दो पुलिस वालों पर हमला करने का फैसला किया. जब दोनों पुलिस जवान गपशप में मस्त थे, तब हमारे जांबाज योद्धाओं ने पीछे से जाकर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. अचानक और बिजली जैसी तेजी से की गई वारों से एक पुलिस वाला सम्भल ही नहीं पाया जो वहीं ढेर हो गया. जबकि दूसरा अपना हथियार छोड़कर जान हथेली पर रखकर भाग खड़ा हुआ. पीएलजीए के आधार बल के हमारे जन सैनिकों ने दो एसएलआर और 90 गोलियां लेकर लौट गए. हालांकि वापस आते समय जब वे एक सड़क पार कर रहे थे तब पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं पर वे सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल लौट गए. जिला मुख्यालय होने के बावजूद और सैकड़ों पुलिस वालों की तैनाती के बावजूद इन कॉमरेडों ने शानदार पहलकदमी दिखाई. इस कामयाब हमले से यह सचाई फिर एक साबित हो गई कि जब पहलकदमी अपने हाथ में हो और जनता पर निर्भर करते हुए सूझबूझ व साहस के साथ काम लें तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना को एक कमजोर सेना भी परास्त कर सकती है.

बेलचर के निकट सीआरपीएफ पर एम्बुश 5 जवानों का सफाया 7 घायल

निरीह ड्राइवर की हत्या – सीआरपी वालों की कायराना हरकत

23 मई को पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने पश्चिम बस्तर डिवीजन के भैरमगढ़ तहसील में बेलचर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया. दरअसल ये आतंकी जवान एक गोपनीय कार्रवाई के तहत बीजापुर से निकले हुए थे. तभी उनके एक वाहन को पीएलजीए के सैनिकों ने बारूदी सुरंग से उड़ा दिया. उसके बाद उन पर जमकर गोलीबारी की. विस्फोट और गोलीबारी में कुल पांच जवान मारे गए और 7 घायल हो गए.

इससे बौखलाए सीआरपी जवानों ने वहां से तभी गुजर रहे एक ट्रैक्टर को रोका और ड्राइवर देवनाथ (22) को गोली मार दी. बाद में पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मारा गया नक्सली बताया. दरअसल देवनाथ भैरमगढ़ का निवासी था और पीएलजीए के हमले से उसका कोई लेना–देना नहीं था. लोगों में दहशत फैलाने की मंशा से सीआरपीएफ ने जानबूझकर यह जघन्य हत्या की. 'प्रभात' इस हत्या की कड़ी निंदा करती है और मृतक के शोकसंतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है.

सरगुजा में मुठभेड़ – थानेदार का सफाया

सरगुजा जिले के डाडकेसरा गांव में पीएलजीए का एक दस्ता ठहरा हुआ था. वह गांव के लोगों से मीटिंग ले रहा था. अपने मुखबिर के जरिए खबर पाकर मैनपाट थानेदार कजूर के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पीएलजीए दस्ते को घेरकर हमला करने की कोशिश की. लेकिन सतर्क संतरी ने पुलिस को देखते ही फायर खोल दिया. बाद में सारे कॉमरेडों ने जमकर गोलीबारी की जिसमें थानेदार कजूर की मौत हुई. इस हमले ने जहां पुलिस का मनोबल बुरी तरह गिरा दिया, वहीं जनता में आत्मविश्वास बढ़ा दिया.

विंजरम एम्बुश में सीआरपीएफ के 6 जवान मरे और कम से कम 9 घायल

1 जून को दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा तहसील के विंजरम गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीएलजीए सैनिकों ने एक जबर्दस्त हमला किया. जब भेज्री थाने से सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला कोंटा जा रहा था, तो ताक में बैठे छापामारों ने हमला बोल दिया. उनके एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया और बाद में गोलीबारी की. इसमें कुल 6 जवान मारे गए और 4 घायल हो गए. बाद में इनकी मदद में आ रही पुलिस वालों पर पीएलजीए की एक और टुकड़ी ने एम्बुश किया जिसमें 5 अन्य पुलिस वाले घायल हो गए. इस हमले से पुलिस बलों में इतनी दहशत भर गई क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में भी वे सुरक्षित नहीं है.

बेवरटोला के निकट पीएलजीए का हमला दो थानेदार समेत 7 पुलिस वाले मरे

दुश्मन के सारे हथियारों पर पीएलजीए का कब्जा

महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बेवरटोला गांव की याद आते ही हम सभी के मन में वहां की चार निरीह युवतियों की जघन्य हत्या की याद आती है. वहशीपन और दरिंदगी से सराबोर पुलिस वालों ने 1994 में इस गांव की चार किशोरियों को गिरफ्तार कर, उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर बाद में उनकी हत्या की थी. अपनी इस नीचतापूर्ण कार्रवाई को हमेशा के लिए दफनाने की मंशा से पुलिस ने उन लड़कियों की लाशें गुपचुप से जमीन में गाड़ दीं और बाद में यह कहना शुरू किया कि उसने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया. इस पर मानवाधिकार संगठनों ने अदालत में जाकर संघर्ष किया. लेकिन आंखों पर काली पट्टी पहनने वाली अंधी 'न्यायदेवता' ने पुलिस को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. बेवरटोला और उसके आसपास के हर गांव में हर व्यक्ति के सीने में पुलिस के खिलाफ गुस्से की आग लगातार सुलग रही है.

बहर-हाल, उसी बेवरटोला के निकट 30 मई को पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने पुलिस पर एक शानदार हमला किया. इस हमले में दो उप निरीक्षकों समेत 7 पुलिस वाले कुत्ते की मौत मारे गए, जबकि 2 अन्य घायल हो गए. इस हमले से पीएलजीए ने बेवरटोला की चार मासूम लड़कियां - प्रमीला, जयवन्ता, तारा और सुखवंती के खून का शानदार बदला ले लिया. हमले के दौरान पीएलजीए ने दुश्मन के सारे हथियार छीन लिए जिनमें कुछ एके-47 और एसएलआर शामिल हैं. इसके अलावा एक वॉकीटॉकी सेट भी छीन ली.

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में पीएलजीए का हमला

एक पुलिस जवान मरा - एक घायल

3 जून को पीएलजीए की एक टुकड़ी ने बालाघाट जिले की बंजारी घाटी में एक पुलिस दल पर हमला बोल दिया. इस हमले में मोटार सायकिल पर सवार एक पुलिस कर्मी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मौटर सायकिल 15 फीट दूर जा गिरी थी. पुलिस ने माना है बालाघाट जिले में पिछले कुछ महीनों में यह पहली बड़ी कार्रवाई थी.

गोपनीय सैनिक हनुमंत का सफाया

3 अप्रैल को दक्षिण बस्तर डिवीजन के दोरनापाल कस्बे में सीआरपीएफ कैम्प के निकट पीएलजीए की एक एक्शन टीम ने गोपनीय सैनिक हनुमंत को मार गिराया. घटना स्थल से सीआरपीएफ का कैम्प महज 300 मीटर की दूरी पर था. पिछले 6-7 सालों से पुलिस का दलाल बनकर गोपनीय सैनिक के रूप में काम कर रहा हनुमंत का सफाया करके पीएलजीए के लाल योद्धा नारे लगाते हुए कुशलतापूर्वक लौट गए. इस हमले के बाद बौखला गए सीआरपीएफ जवानों ने आम लोगों पर डंडे बरसाकर अपना गुस्सा उतार लिया. अपनी नाकामी को छिपाने की मंशा से की गई इस नीचतापूर्ण हरकत की शहर के लोगों ने कड़ी निंदा की.

सरगुजा जिले के भटगांव चौकी पर पीएलजीए का हमला

भारी मात्रा में हथियार व गोलाबारूद जब्त

28 अप्रैल को शाम के करीब सात बजे पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने सरगुजा जिले के भटगांव चौकी पर अचानक हमला कर दिया. जब तक पुलिस इसे समझ पाती और होश में आ जाती तब तक पीएलजीए ने काम तमाम कर दिया. दो वाहनों में सवार होकर पीएलजीए सैनिकों ने बीच बस्ती में चौकी इस चौकी पर बड़ी सूझबूझ व शूरता के साथ हमला बोल दिया. इस घटना में चार पुलिस कर्मी घायल हो गए जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि इस हमले के बाद माओवादी छापामार चौकी से 4 एसएलआर, 4 अन्य रायफलें, कुछ जब्त किए गए हथियार और 800 से ज्यादा गोलियां उठा ले गए. लेकिन चर्चा यह भी चल रही थी कि पुलिस ने छीने गए हथियारों की संख्या कम बताई है.

कुटरू के पास हमला - 2 सीआरपी जवान घायल

4 मई को पश्चिम बस्तर डिवीजन के कुटरू के पास सुबह के साढ़े 10 बजे पीएलजीए सैनिकों ने एक बारूदी सुरंग का विस्फोट किया जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान बुरी तरह घायल हुए. मिली खबरों के मुताबिक इस घटना के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी भी हुई.

कापसी के निकट हमला - 5 जवान घायल

25 अप्रैल को उत्तर बस्तर डिवीजन के कापसी के निकट पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने पुलिस के वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ाने की कोशिश की. लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हुई. हालांकि इस घटना में 5 पुलिस वाले घायल हो गए. दरअसल पीएलजीए ने इस हमले के एक दिन पूर्व चालीकोटरी गांव में वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ की थी ताकि पुलिस का ध्यान आकर्षित किया जा सके. योजना के मुताबिक पुलिस जांच करने आई भी थी और जब वह लौट रही थी तो पीएलजीए ने यह हमला कर दिया.

ताडोकी हाट बाजार में हमला - 2 सीआरपी जवान मरे

मई के पहले सप्ताह में उत्तर बस्तर डिवीजन के ताड़ोकी बाजार में पीएलजीए के सैनिकों ने एक बारूदी सुरंग का विस्फोट कर सीआरपीएफ के 2 जवानों को मार गिराया, एक को घायल किया. ✶

शत्रु दमन को धता बताते हुए जनता का क्रान्ति की राह पर आगे कदम

दण्डकारण्य की जनता अपने संघर्ष को जारी रखते हुए आए दिन नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रही है. इस बीच पुलिस दमन में भारी-भरकम इजाफा हुआ है. अर्द्ध-सैनिक बलों के गश्त व तलाशी अभियान तथा 'घेराव-दमन' अभियान जोरों पर चल रहे हैं. नए-नए थानों व चौकियों का निर्माण किया जा रहा है. लोगों को पकड़ना, मारना, जेल में डालना, बलात्कार, आदि घटनाएं बढ़ीं. इसके बावजूद लोगों ने संघर्ष का परचम ऊंचा रखा हुआ है. इनमें अपनी मांगों को हासिल करने के लिए किए गए संघर्ष भी हैं और पंचायत चुनावों का बहिष्कार, 26 जनवरी का बहिष्कार जैसे राजनीतिक संघर्ष भी हैं. इसके अलावा 20 से 23 तारीख तक दण्डकारण्य में 'साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस' भी मनाए गए. इस मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. 15 से 21 मई तक 'दमन विरोधी सप्ताह' मनाया गया. 10 फरवरी को 'भूमकाल दिवस' मनाया गया और 8 मार्च - अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन भी बड़े पैमाने पर किया गया. सरकारी व जन विरोधियों की सम्पत्तियों को तबाह किया गया. मुखबिरों व पुलिस बलों का सफाया किया गया. इन सभी संघर्षों और कार्यक्रमों में जनता ने हजारों की तादाद में भाग लिया. दण्डकारण्य की संघर्षशील जनता का 'प्रभात' लाल अभिनन्दन करता है. इसके सम्बन्ध में हमें जितनी रिपोर्टें प्राप्त हुईं, उनका सार-संकलन हम यहां पेश कर रहे हैं. अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमें ज्यादा रिपोर्टें नहीं मिल पाईं.

– सम्पादकमण्डल

पंचायत चुनावों का बहिष्कार

पश्चिम बस्तर डिवीजन

नेशनल पार्क इलाके में जनवरी 23 को प्रस्तावित पंचायत चुनावों का बहिष्कार का आह्वान करते हुए बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया. पोस्टर, बैनर लगाए गए. पूरे इलाके में पुराने सरपंचों व सचिवों के साथ-साथ नए फारम भरने वालों को बुलाकर जनता के समक्ष चर्चा की गई. इसमें जनता ने उनसे सवाल किए कि इतने सालों से तुम लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है. जनता का धन लूटकर किसी ने शहर में बंगला बना लिया तो किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया. सिवाए इसके किसी भी नेता ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया. इस लुटेरी व्यवस्था के तहत होने वाले चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करने का नारा देकर लोगों ने सभा का समापन किया. इस मौके पर जनता ने गांव-गांव में *जनताना सरकार* की स्थापना करने का संकल्प दोहराया.

इस संदर्भ में कोम्पाल में आयोजित सभा में 836 लोगों ने भाग लिया जो 12 गांवों से आए हुए थे. मरियल में 1385 , वूरेनार में 1200, सागुमेट्टा में 260, केरपे में 200 और सेंड्रा में 200 लोगों ने सभाओं में भाग लिया जहां रैलियां निकाली गईं. इस प्रचार अभियान के असर से कुछ लोगों ने अपना पर्चा वापिस लिया जिन्होंने नामांकन दाखिल किया हुआ था.

इस इलाके में चुनाव के मौके पर विपक्षी नेता महेन्द्र कर्मा ने कुछ गांवों में अपने आदमियों को पैसा बांटा था. मतदान के दिन पुलिस बलों ने जनता को डरा-धमकाकर वोट डलवाया. इसके बावजूद भी जनता ने बड़ी संख्या में इन चुनावों का बहिष्कार किया. सागुमेट्टा, सेंड्रा, केरपे, कुंगिलेर, करकेली, बोदिली, मोरिमेल, तोयनार, चिन्तल, बंदेपर, आदि गांवों में जन मिलिशिया सदस्यों ने मतपेटियों को छीनकर जला डाला. मतपेटियां लाने वाले वाहनों और प्रचार में आने वाले वाहनों को जला डाला.

मद्देड एरिया में पंचायत चुनाव का बहिष्कार सफल रहा. एरिया सीएनएम दल और डिवीजन दल के साथ-साथ विभिन्न जन संगठनों को बहिष्कार हेतु प्रचार का कार्यक्रम सौम्पा गया. पूरे एरिया में पोस्टर-बैनर लगा दिए गए. आवपल्ली एलजीएस के दायरे में मूंजलकांकेर गांव में आयोजित एक सभा में 1 हजार लोगों ने भाग लिया. पूसगूडि और राल्लापल्ली में आयोजित सभाओं में 600 लोगों ने भाग लिया. धनगोल में 500 लोगों ने सभा में भाग लिया. इन सारी सभाओं में पुराने पंच-सरपंचों को बुलाकर उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया. जिन लोगों ने नामांकन भर दिया उन्हें समझा-बुझाकर वापिस लेने पर बाध्य किया गया. लोगों में यह संदेश फैलाया गया कि चूंकि पंचायत व्यवस्था भी लुटेरी व्यवस्था का अंग है, इसलिए इसका बहिष्कार करके गांव-गांव में *जनताना सरकार* की स्थापना की जाए. मतदान के दिन बहुत कम मतदान हुआ है.

संकेनपल्ली, मुरदोंडा, शरमंगी, चेरुकुल, आदि गांवों में मिलिशिया यूनिटों ने मतपेटियां छीन लीं. पुनर मतदान संकेनपल्ली छोड़कर कहीं भी न हो सका. पुनर मतदान के दिन 60-70 पुलिस वाले आए थे और दो घण्टे के अन्दर ही मतदान की रस्म आधी-अधूरी पूरी करके चले गए. कुल मिलाकर इस इलाके में चुनाव बहिष्कार सफल रहा.

शराब भट्टी पर धावा

गड़चिरोली डिवीजन के सिरोंचा एरिया में 2 जनवरी को स्थानीय छापामार दस्ते ने चीटूर गांव के पास स्थित शराब भट्टी पर हमला कर करीब 10 हजार रुपए की शराब को नष्ट कर दिया. अंकिसा गांव का चीमला सम्मय्या नामक शराब ठेकेदार पिछले 3-4 सालों से यह अवैध धंधा कर रहा था. शुरू में पुलिस ने इसे मना कर दिया था तो इसने 10 हजार रुपए की घूस खिलाई. इसके अलावा जब भी पुलिस कमाण्डो गश्त पर आते हैं तो उन्हें यह दारू पिलाया करता था और बकरा-मुरगा काटकर दावत दिया करता था. इस तरह पुलिस के संरक्षण में सम्मय्या का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी के रफ्तार से बढ़ रहा था. इस शराब में यूरिया, अम्मोनियम जैसे रासायनों का इस्तेमाल

करने से इसका सेवन करने वाले लोगों को कई बीमारियों से दो–चार होना पड़ रहा था. जनता इसका विरोध करती थी पर पुलिस के संरक्षण होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी. इस इलाके में जारी भारी दमन के चलते जनता खुलकर लड़ाई में भाग लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी. ऐसी प्रतिकूल स्थिति में छापामार दस्ते ने जनता की सक्रिय मदद से शराब भट्टी को तोड़ डाला.

सड़क ठेकेदार व जन दुश्मन बंडारी वेंकटी का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के सिरोंचा तहसील के बामिनी गांव के निकट पीएलजीए के दस्ते ने 9 जनवरी को जनता की सक्रिय मदद से ठेकेदार वेंकटी का सफाया कर दिया. दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी संगठनों ने सड़क निर्माण के कामों को मना कर रखा है. इसके बावजूद इसने काम जारी रखा था. काम करने वाले मजदूरों को ठगने में भी यह माहिर था. जिनगनूर गांव के लोगों ने 3 महीने काम किया था तो इसने उन्हें एक कौड़ी भी नहीं दी. वेंकटी लुटेरी राजनीति में भी दखल रखता था. ठेकेदारी, पैरवी, आदि कामों में लोगों को लूट–ठगकर इसने लाखों सम्पत्ति कमा रखी थी. पिछले साल अक्टूबर में सम्पन्न विधानसभा चुनावों के मौके पर जन संगठनों ने बहिष्कार का आह्वान दिया था. पर वेंकटी ने इसका उल्लंघन करते हुए कांग्रेस को जिताने के लिए न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि पैसा भी बांटा था. वोट न डालने पर पुलिस को बताकर जेल में डलवा देने की धमकियां देकर इसने लोगों पर दबाव डाला था. इन तमाम हरकतों और उसके जन विरोधी आचरण को देखते हुए इस इलाके की जनता और जन संगठनों ने इसे मौत के घाट उतारने का फैसला ले लिया.

जनता द्वारा अकाल हमला – 50 क्विंटल चावल जब्त

अहेरी इलाके के वेनुकाबंडा गांव में पानलोट संस्था द्वारा रखे गए 50 क्विंटल चावल जनता ने 26 दिसम्बर 2004 को जब्त कर लिया. इस इलाके की जनता सूखे से बुरी तरह प्रभावित थी. सरकार कागजों पर तो सूखा–पीड़ित लोगों के नाम पर ढेर सारी योजनाएं तैयार कीं, पर उसका लाभ गरीब आदमी को कभी नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में सरकारी योजनाएं जनता को गुमराह करने के ही काम आती हैं. सरकार की दिवालिया नीतियों का विरोध करते हुए इलाके के 5 गांवों के लोगों ने यह हमला किया.

लोगों ने अपने संगठन नेता को पुलिस के चंगुल से छुड़वा लिया

गड़चिरोली जिले में पुलिसिया दमन और अत्याचारों की हद ही नहीं रह गई. लेकिन इस घुटन भरे माहौल में भी लोगों ने बगावत का परचम मजबूती से थाम रखा है, इसका एक उदाहरण है गांव चेल्लावाड़ा में घटी एक घटना. 25 पुलिस वालों के एक दल ने गांव पर धावा बोला और संगठन के एक नेता को गिरफ्तार कर लिया. बाद में इस गांव की महिलाओं समेत कुल 40 लोगों ने थाने के सामने धरना दिया. उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि उस व्यक्ति को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. जनता ने यह ठान ले रखी थी कि जब तक पुलिस गिरफ्तार नेता को छोड़ नहीं देती तब तक वह वहां से नहीं हिलेगी. जनता की एकजुटता और मजबूत इरादों को देखकर पुलिस को झुकना ही पड़ा.

26 जनवरी को 'काला दिवस' मना

अहेरी इलाके के तीन गांवों के 40 लोगों ने एक जगह पर झूठे गणतंत्र दिवस का विरोध करते हुए 'काला दिवस' मनाया. इस मौके पर पार्टी एरिया कमेटी सचिव ने लोगों को सम्बोधित किया. 26 जनवरी को उन्होंने 'काला दिवस' ठहराते हुए कहा कि पिछले 55 सालों में हमारे देश में कोई विकास नहीं हुआ. बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, महिलाओं के साथ भेदभाव, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले, आदिवासियों और दलितों के कत्लेआम – इन्हीं में 'विकास' हो रहा है. भ्रष्टाचार और अत्याचार का हर तरफ बोलबाला है. ऐसे समाज को बदले बिना गरीबों को सच्चे अर्थों में आजादी नहीं मिल सकती. उन्होंने सभी उपस्थित जनता का आह्वान किया कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में जारी क्रान्तिकारी संघर्ष में शामिल हो जाए.

जन मिलिशिया के हाथों होमगॉर्ड लचुमैया का सफाया

पश्चिम बस्तर डिवीजन के नेशनल पार्क इलाके के फरसेगढ़ का निवासी पोंदि लचुमैया पिछले 12 सालों से पुलिस थाने में होमगॉर्ड की नौकरी कर रहा था. पुलिस जब भी संघर्ष इलाकों में गश्त पर निकलती है तो रास्ते दिखाने के लिए लचुमैया उसके साथ रहा करता था. हाट बाजार में जाने वाले लोगों की तलाशी लिया करता था. इसके पहले 1988 में मूकवेल्ली गांव में हुई मुठभेड़ के लिए भी यही जिम्मेदार था, जिसमें कॉमरेड कुरसम राजक्का शहीद हुई थीं. इसका सफाया करने के लिए जन मिलिशिया ने कई बार कोशिश की थी. खतरे को भांपकर लचुमैया ने थाने में ही खाना–सोना शुरू किया. आखिरकार जन मिलिशिया ने 26 अप्रैल को होली के दिन सही योजना बनाकर इसका सफाया कर दिया.

पुलिस मुखबिर बुधू और सुखनाथ का सफाया

पश्चिम बस्तर डिवीजन के तोयनार गांव का निवासी बुधू, धनोरा का निवासी सुखनाथ दोनों ही पिछले कुछ अरसे से मुखबिरी कर रहे थे. तोयनार गांव से होमगॉर्ड बने एक व्यक्ति ने इन्हें पैसे देकर मुखबिर बना लिया. जब दस्ता आता है, खासकर नेतृत्वकारी कॉमरेड आते हैं तो उसे उसकी सूचना देने कहा गया था. ये दोनों आसपास के गांवों में घूमकर संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखा करते थे. पिछले साल अगस्त में छापामारों ने एक जगह कैम्प किया था तो इन मुखबिरों ने पुलिस को इत्तला दिया था. दस्ते के कैम्प खाली करने के 10 मिनट बाद पुलिस पहुंची, जिससे मुठभेड़ टल गई. अक्टूबर महीने में भी ये दोनों एक गांव में दस्ते का पता लगाने आए थे. तब इन्हें छापामार दस्ते ने पकड़ कर चेतावनी देकर छोड़ दिया था. बाद में भी कोई सुधार न आते देख पार्टी और जन संगठनों ने इनका सफाया करने का फैसला लिया, जिसे 8 नवम्बर को अमल किया गया.

नूकनपल्ली में मुखबिर गट्टी का सफाया

पश्चिम बस्तर डिवीजन के नूकनपल्ली गांव में पटेल का परिवार शुरू से ही जालिम परिवार रहा. गांव में इन्हीं की तूती बोलती थी. इनके परिवार से गट्टी नामक व्यक्ति मुखबिर बन गया. इसका भाई सरपंच था. गट्टी पुलिस के साथ घूमते हुए रास्ते दिखाया करता था. जन संगठन सदस्यों के नाम बताया करता था. पुलिस के साथ इसके सम्बन्धों के बारे में सभी को मालूम होने के बाद इसने बीजापुर में डेरा जमाया और एसपी का मुंह चढ़ा बन गया. एक बार जब इसने गुप्त रूप से अपने गांव का दौरा किया तब छापामार दस्ते ने पकड़ लिया. पहले तो इसने अपना नाम दूसरा बताकर बचने की कोशिश की पर बाद में असलियत पता चल गई. जब इससे पूछताछ की जा रही थी तब किसी तरह भाग गया था. बाद में फिर इसे एक जातरा के दौरान छापामार दस्ते ने पकड़ कर मार डाला.

अंधविश्वास से हत्या करने वालों पर जन अदालत

भैरमगढ़ विकासखण्ड के मिरतुल एरिया के जांगला गांव के सरपंच ने उसी गांव के माडवी बुधू की हत्या करवाई थी. सरपंच के कहने पर दो व्यक्तियों ने यह काम किया था. हत्या का कारण अंधविश्वास था. वे बुधू को टोनहा समझते थे. लोगों ने इस हत्या के बारे में डीएकेएमएस को बताया तो इस पर जन अदालत चलाने का फैसला हुआ. जन अदालत में यह तय हुआ कि मृतक के परिवार जनों को हत्या करवाने वाले और करने वाले मिलकर 6 हजार रुपए का मुआवजा दें. इस मौके पर लोगों को समझाइश दी गई कि अंधविश्वासों को त्याग दें और टोनही के नाम पर किसी की हत्या न करें. लोगों को समझाया गया कि बीमार होने पर अस्पताल जाना चाहिए.

हत्यारों को सजा

इसी इलाके के अलवूर गांव के निवासी बुधराम की हत्या मार्च 2004 में तब हुई थी जब वह मेले से लौट रहा था. लाश को घटना स्थल से दूर फेंका गया था. अलवूर गांव के लोगों ने इस बारे में स्थानीय छापामार दस्ते को बताया. दस्ते ने इसे निपटने का जिम्मा डीएकेएमएस को सौम्पा. जांच में पता चला कि यह हत्या पोंदु गांव के कुछ व्यक्तियों ने की. हुआ यूं कि पोंदु गांव की सोमली नामक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन उसी गांव के एक व्यक्ति से की गई थी. लेकिन वह लड़की अपने माइके भाग गई. उसके ससुराल वाले उसे फिर ले गए. वह फिर भागी. इस तरह यह सिलसिला 3 साल लगातार चला. बाद में सोमली ने इससे तंग आकर अलुवूर गांव के बुधराल के घर जाकर बस गई. इससे गुस्साए पोंदु वालों ने या तो बुधराम की या फिर दोनों की हत्या करने की धमकियां दीं. पर बुधराम नहीं डरा था. हालांकि दो बार उसकी हत्या की कोशिशें की गईं. वह कहीं भी अकेला नहीं जाता था. लेकिन मेले के समय वह जब अकेला था, हत्या का शिकार हो गया. डीएकेएमएस ने इस पर गांव में चर्चा करके यह फैसला सुनाया कि हत्यारों की पिटाई की जाए और वे 6 हजार रुपए का मुआवजा दें.

दमन के खिलाफ रैली

दिसम्बर 2003 में सत्तारूढ़ हुए रमन सिंह ने संघर्ष इलाकों में सीआरपीएफ, एसटीएफ जैसे सशस्त्र बलों को बड़ी संख्या में तैनात कर भारी दमन अभियान छेड़ रखा है. झूठी मुठभेड़ें, गिरफ्तारियां, गांवों पर छापेमारियां, आदि आम हो चुकी हैं. पुलिस बल घरों में घुसकर लोगों के अनाज को भी नष्ट कर रहे हैं. इसके खिलाफ पूरे दण्डकारण्य में 2004 सितम्बर 21 से 27 तक दमन विरोधी रैलियां निकालने का फैसला लिया गया.

इस आह्वान को पाकर इलाके के सभी पार्टी, फौजी व जन संगठनों ने व्यापक प्रचार अभियान चलाया. सड़कों, स्कूल भवनों पर दीवार-लेखन की. भैरमगढ़ इलाके में कुल 13 जगहों पर आम सभाएं हुईं जिनमें कुल 25,724 लोगों ने भाग लिया. इनमें स्कूली बच्चे और महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थीं. इन सभाओं को डीएकेएमएस, केएएमएस व भाकपा (माओवादी) के स्थानीय नेताओं ने सम्बोधित किया. लोगों ने दमन की निंदा की. सीएनएम टोलियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. हालांकि 27 सितम्बर को बीजापुर में रैली के लिए 8 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, पर पुलिस बलों ने उसे रोक दिया.

भाजपा सरकार के ढोंगी सुधारों के खिलाफ

भैरमगढ़ इलाके के सभी गांवों में जन संगठनों और पार्टी संगठनों ने सरकारी सुधारों के खिलाफ जनता में प्रचार अभियान चलाया. 25 पैसे में किलो नमक, हर परिवार को एक भैंस, 10वीं पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सायकिल, काम के बदले अनाज जैसी लोक लुभावन योजनाओं से सरकार जनता को वर्ग संघर्ष के रास्ते से अलग करना चाह रही है. आखिरकार इन योजनाओं का असली फायदा तो आम लोगों को नहीं मिल रहा है. ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, सचिव, आदि सरकारी अधिकारियों और तथाकथित जन प्रतिनिधियों की सम्पत्तियां बढ़ती जा रही हैं. लोगों को समझाया गया कि सुधारों के रास्ते नहीं क्रान्ति के रास्ते ही समाज को बदला जा सकता है तथा लूट को जड़ से मिटाया जा सकता है.

भैरमगढ़ इलाके में भूमि-संघर्ष

पश्चिम बस्तर डिवीजन के बीजापुर कस्बे से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित 85 एकड़ जमीन पर 1973 में तत्कालीन सरकार ने कब्जा किया था. इसमें वानस्पतिक व कृषि विभागों ने फलों और फूलों के पौधे उगाए थे. इस बगीचे में एक बड़ा तालाब है और 25 एकड़ उपजाऊ जमीन है जोकि पिछले कुछ सालों से पड़ती रखी हुई है. आसपास के गांवों में जन संगठन मजबूत होने के बाद 5 गांवों के भूमिहीन लोगों ने इस जमीन की सामूहिक खेती की और उपज को बांट लिया. इस साल तालाब में मछली पालने के इरादे से लोगों ने सामूहिक रूप से 15 किलो बीज लाकर डाले.

इसी इलाके में एक और तालाब है जिसे सिंचाई विभाग ने 2003 में बनावाया था. गांव के कुछ मुखियाओं ने इसे अपने कब्जे में रखकर मछलियों से होने वाली पूरी आमदनी को खुद ही हड़पना शुरू किया था. गांव में डीएकेएमएस ने फैसला किया कि यह तालाब गांव की

जनता का सामूहिक सम्पत्ति के रूप में रहेगा. गांव के सामूहिक कोष से 7 किलो मछली के बीज लाकर तालाब में छोड़ा गया. इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों को अपने स्वार्थ के लिए कब्जे में लेने वाले मुखियाओं के खिलाफ डीएकेएमएस ने संघर्ष तेज किया.

चार लकड़ी डिपों को तबाह

गड़चिरोली डिवीजन के जिम्मलागट्टा एरिया में पीएलजीए सैनिकों ने लकड़ी के 4 डिपो जला दिए जिससे सरकार को तकरीबन 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ. यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि पिछले कई सालों से जंगल कटाई पर क्रान्तिकारी संगठनों द्वारा पाबन्दी लगाए जाने के बावजूद वन विभाग पुलिस बलों के सहारे जंगल कटवा रहा है. वन विभाग के कार्पोरेशन द्वारा की गई क्लीयर फेल्लिंग से आल्लापल्ली से लेकर जिम्मलागट्टा तक पूरा जंगल साफ हो गया. इससे जंगल पर ही निर्भर रहकर जिन्दगी गुजारने वाले हजारों आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट छा गया. मना करने के बावजूद जंगल को मनमाने ढंग से कटवाकर उलटा आदिवासियों पर यह दोष मढ़ना कि वे ही जंगल को बरबाद कर रहे हैं, वन विभाग की आदत बन गया है. इसलिए वन विभाग के अधिकारियों को सबक सिखाने के इरादे से जनता की आकांक्षा के मुताबिक पीएलजीए दस्ते ने यह कार्रवाई की.

'गुरूजी' बनकर मुखबिरी करने वाले सिरिया कुडिमेत के खिलाफ जन अदालत

गांवों में मुखबिर तैयार करने के लिए पुलिस तरह-तरह के हथकण्डे अपना रही है. उन्हें गुरूजी, आंगनवाड़ी शिक्षिका, मलेरिया बाबू बनाकर गांवों में भेज रही है ताकि वे गुप्त रूप से मुखबिरी कर सकें. गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी इलाके के कल्लेडा गांव का निवासी सिरिया कुडिमेत पढ़ाई के सिलसिले में अहेरी कस्बे में रहने लगा था. तभी उसकी मुलाकात कमाण्डो अरुण आत्रम से हुई. आत्रम ने पैसे का लालच देकर सिरिया को मुखबिर बना लिया. कल्लेडा गांव शुरू से क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थक गांव रहा है. दुश्मन की नजर भी इस गांव पर हमेशा रहती है. इसीलिए उसने इस गांव से आखिरकार एक मुखबिर बना ही लिया. 11 जनवरी 2005 को छापामार दस्ता कल्लेडा गांव गया था. जब गांव वालों के साथ मीटिंग चल रही थी तब सिरिया सायकल पर देशिलपेट थाना गया और पुलिस को दस्ते की सूचना दी. लेकिन जब तक पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती तब तक छापामार दस्ता वहां से निकल जा चुका था. सो एक मुठभेड़ टल गई थी. हालांकि पुलिस ने अपना गुस्सा उतारने के लिए लोगों के साथ गाली-गलौज किया और धमकियां दीं. इसके बाद जांच की गई तो पता चला कि यह करतूत सिरिया की थी. जन अदालत में इस पर चर्चा की तो ग्रामवासियों ने सिरिया की हरकत की घोर निंदा की. खुद उसके पिता, मां, बड़े पिता, दादा और पत्नी ने इसका जमकर विरोध किया. लोगों ने कहा कि 25 सालों से पार्टी और क्रान्ति के साथ इस गांव का जो बढ़िया रिश्ता रहा उस पर सिरिया ने कालिख पोत दिया.

सिरिया को क्या सजा दी जाए, इस पर चर्चा करने से सभी लोगों ने एक बार के लिए इसे माफ करने का फैसला किया. दुबारा ऐसी हरकत करेगा तो उसे जान से खत्म करने की चेतावनी के साथ जन अदालत ने उसे जिन्दगी बख्श दी.

मुखबिर रामैया सडिमेक का सफाया

सिरोंचा इलाके के मेट्टुगूडेम गांव का रामैया काफी समय से पुलिस मुखबिरी कर रहा था. इसका भाई हनमंतु सरपंच पद पर है. सरकार से मिलने वाले पैसों में दोनों भाई हेराफेरी करते थे. जनवरी 2005 में एक बार रामैया ने एक गांव में दस्ते के रहने की सूचना पुलिस को दी थी. पर चूंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से दस्ता खिसक चुका था, इसलिए मुठभेड़ टल गई. बाद में इसकी जन विरोधी हरकतों पर पूरी जांच करके जनता की सहमति से पीएलजीए की एक्शन टीम ने इसका सफाया किया.

पुलिस में इंटरव्यू देने वालों के खिलाफ जन अदालत

गड़चिरोली डिवीजन के एटापल्ली इलाके के घोटसुर गांव में पहले पुलिस थाना रहा करता था. तभी इस गांव से तीन युवक पुलिस में भर्ती हो गए. उन्होंने गांव वालों को परेशान कर रखा है. हाल ही में उन्होंने गांव से 5 और लोगों को पुलिस में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया. इनमें तीन लड़कियां और दो लड़के थे. खासकर गड़चिरोली जिले में स्थानीय युवक-युवतियों को पुलिस व कमाण्डो बलों में भर्ती करने का सिलसिला पहले से जारी है. अपनी ही उंगलियों से अपनी आंखों को फोड़वाने के लिए सरकार ने यह नीचतापूर्ण तरीका अपनाया हुआ है. इसके तहत कुछ भोले-भाले लड़के भी पैसे के लालच में आकर पुलिस में जा रहे हैं. हालांकि जनता और जन संगठन इसके खिलाफ काफी प्रचार कर रहे हैं. घोटसूर गांव में भी इसका पता चल जाने के बाद जनता की एक मीटिंग चलाई गई. मीटिंग में जन संगठन नेताओं ने पुलिस में भर्ती होने से होने वाले नुकसानों के बारे में समझाया. उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. गांव के सभी लोगों ने उन्हें पुलिस में जाने से मना कर दिया.

बूरगी सरपंच का सफाया

ग्राम बूरगी में पुलिस पटेल परिवार का सदस्य रामा नरोटी सरपंच का काम कर रहा था. सरपंच का काम करते-करते वह पुलिस मुखबिर बन गया. एक बार गांव में छापामारों की एक टीम गई तो उसने पुलिस को खबर दी थी. लेकिन पुलिस को पहले ही देख चुके दस्ता सदस्य वहां से हट गए थे. उसका एक छोटा भाई पुलिस के पास काफी अरसे से रह रहा था. उसकी कथित चिट्ठियां लेकर रामा गांव-गांव घूमकर दस्ते का पता लगाता था. एक बार उस इलाके में छापामारों ने एक कैम्प करने की कोशिश तो रामा ने पुलिस को उसकी खबर दी. उस समय पुलिस ने तीन कॉमरेडों पर गोलीबारी की, हालांकि उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था. वहां कैम्प नहीं हो पाया था. इसकी तमाम करतूतों की जांच करने के बाद पार्टी ने जनता की सहमति से रामा का सफाया करने का फैसला लिया. 28 मार्च को इस दलाल को मौत के घाट उतार दिया गया. ✶

सभा – सम्मेलन

संघर्ष की कामनाओं के साथ मना 'भूमकाल दिवस'

गड़चिरोली डिवीजन

गड़चिरोली डिवीजन के ताड़िगाम रेंज माडवेल्ली गांव में 'भूमकाल संघर्ष' की याद में 10 फरवरी के दिन एक सभा आयोजित की गई. इस सभा में 35 स्त्री–पुरुषों ने भाग लिया. केएएमएस की कॉमरेड सुशीला ने झण्डा फहराकर इसका प्रारम्भ किया. सभा को सम्बोधित करते हुए स्थानीय पार्टी कमेटी सचिव ने लोगों को भूमकाल संघर्ष का इतिहास बताया. उन्होंने कहा कि यहां गड़चिरोली जिले के सूर्जागढ़ इलाके में सेडिमेक बाबूराव के नेतृत्व में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ महान संघर्ष चलाया था. उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाने वाले वीर शहीद गेंदसिंह, गुण्डादुर, बाबूराव समेत तमाम वीरों को श्रद्धांजली पेश की.

बाद में कॉमरेड नवीना ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आदिवासी वीरों द्वारा किए गए संघर्षों को लुटेरे शासक वर्गों ने इतिहास में समुचित स्थान नहीं दिया है. उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आदिवासी विद्रोहों में पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी शानदार भूमिका निभाई थी. आखिर में उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि संघर्ष की शानदार परम्परा को जारी रखते हुए तब तक लड़ाई चलाते रहा जाए जब तक कि हर प्रकार का शोषण और उत्पीड़न का पूरी तरह से अन्त नहीं हो जाता.

गट्टा एरिया में भी भूमकाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता कॉमरेड सरदू ने की. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गुण्डादुर के नेतृत्व में चले भूमकाल विद्रोह के दौरान आदिवासियों ने अपने पारम्परिक हथियारों से लड़कर 40 दिनों तक अपना 'माड़िया राज' चलाया था. आज भी आदिवासी ने संघर्ष जारी रखा हुआ है. फर्क इतना है कि तबकी लड़ाई अंग्रेजी उपनिवेशवादियों के खिलाफ थी, जबकि आज की लड़ाई साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और दलाल पूंजीवाद के खिलाफ है.

कॉमरेड सोनी ने अपने भाषण में कहा कि आज केन्द्र व राज्य सरकारें दण्डकारण्य में जारी जन संघर्ष को कुचलने के लिए तीखा दमन चला रही हैं. हमें 'भूमकाल' संघर्ष को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि सरकारी दमन को हराकर वर्तमान लोकयुद्ध को आगे बढ़ाया जाए. इस कार्यक्रम में कुल 250 लोगों ने भाग लिया जिनमें महिलाओं की संख्या 30 तक थीं.

अहेरी इलाके में दो जगहों पर सभाएं आयोजित की गईं जिनमें 7 गांवों के लोगों ने भाग लिया. सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने भूमकाल संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व पर रोशनी डाली. इन सभाओं में कुल 123 लोगों ने भाग लिया. भूमकाल शहीदों को श्रद्धांजली पेश की गई.

पश्चिम बस्तर डिवीजन

मद्देड इलाके के सभी गांवों में पोस्टर–बैनर लगाए गए. गांव–गांव में प्रचार टोलियों ने व्यापक प्रचार किया. चार गांवों में आमसभाओं का आयोजन किया गया. चिन्ना कोवाल गांव में आयोजित सभा में 400 और एंगपल्ली गांव में आयोजित सभा में 15 लोगों ने भाग लिया. चिर्राकुंटा में 150, पोन्नूर में 150 लोगों ने सभाओं में भाग लिया. इस मौके पर सीएनएम ने एक नाटक पेश किया जिसमें ब्रितानी साम्राज्यवादियों द्वारा भूमकाल संघर्ष को कैसा कुचल दिया गया, इसका चित्रण किया गया. इस मौके पर जनता ने 'भूमकाल संघर्ष जिन्दाबाद', 'गुण्डाधुर को जोहार', 'दुनिया का नम्बर एक दुश्मन अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'गांव–गांव में जनताना सरकार कायम करो', आदि नारे लगाए गए.

भैरमगढ़ इलाके के लोगों ने भी 1910 के भूमकाल संघर्ष को याद किया. उस संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले वीरों को याद किया. पूरे इलाके में भूमकाल दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टरिंग, दीवर–लेखन, बैनर, आदि लगाए गए. 10 फरवरी को मिरतुल इलाके में 2 जगहों पर सभाएं हुईं जिनमें कुल 10 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. जन संगठन नेताओं ने सभाओं को सम्बोधित किया.

पिडिया इलाके में आंडरी और पूंबाड गांवों में सभाएं आयोजित की गईं. पूंबाड में 1910 के भूमकाल विद्रोह में अपनी जान कुरबान करने वाले शहीद दोंडा पेद्दाल की याद में जनता ने श्रम दान के जरिए एक स्मारक का निर्माण किया. इस स्मारक का अनावरण सभा में 20 गांवों से करीब 4 हजार लोगों ने भाग लिया. गंगलूर इलाके में दो जगहों पर सभाएं हुईं जिनमें कुल करीब 6 हजार लोगों ने भाग लिया. इन सभाओं में लोगों ने संकल्प लिया कि भूमकाल शहीदों के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे और साम्राज्यवाद को दफना देंगे. ✶

भैरमगढ़ इलाके में 'भूमकाल दिवस'

सभा – सम्मेलन

दण्डकारण्य में 8 मार्च – अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

गड़चिरोली डिवीजन

टिप्रागढ़ इलाके में 8 मार्च – अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. इस मौके पर पूरे इलाके में पोस्टर लगाए गए और पर्चे बांटे गए. 6 गांव के 390 लोगों ने एक जगह इकट्ठे होकर सभा का आयोजन किया. केएएमएस अध्यक्षा ने केएएमएस का झण्डा फहराकर कार्यक्रम शुरू किया. उन्होंने अपने संबोधन में महिलाओं की समस्याओं पर रोशनी डाली. उन्होंने आह्वान किया कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी सभी अधिकार मिलना है तो संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है.

गट्टा एरिया में 8 मार्च के मौके पर दो जगहों पर सभाएं आयोजित की गईं. इन दोनों सभाओं का संचालन स्थानीय छापामार दस्ते ने किया. दोनों सभाओं में 220 लोगों ने भाग लिया जिसमें महिलाएं करीब 100 थीं. एक सभा में सीएनएम सदस्या कॉमरेड सीमा ने झण्डा फहराकर सभा की अध्यक्षता की. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान क्रान्तिकारी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका का काफी महत्व है. आदिवासी रीति–रिवाज के तहत महिलाओं पर सयानों का दबाव, महिलाओं के साथ अत्याचार, मारना–पीटना, आदि कुरीतियां जारी हैं. इन सबको बदलने के लिए आदिवासी महिलाओं को बड़ी संख्या में केएएमएस में शामिल होकर लड़ना चाहिए.

डीएकेएमएस अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि हम मर्द लोग महिलाओं का दमन करते हैं, उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाते न ही उसे बोलने का अधिकार देते. लेकिन आज जबकि सरकारी दमन जोरों पर चल रहा है, ऐसे में महिलाएं खुद आगे आकर पुलिस का मुकाबला कर रही हैं और अपनी ताकत का परिचय दे रही हैं. उन्होंने मर्दों का आह्वान किया कि महिला को कम न समझा जाए और अपने अन्दर मौजूद पितृसत्तात्मक विचारधारा के खिलाफ लड़ा जाए.

आखिर में सीएनएम कॉमरेडों ने महिलाओं की समस्याओं को लेकर गीत व अन्य कार्यक्रम पेश किए. जनता इस कार्यक्रम से काफी प्रभावित हुए.

अहेरी इलाके में दो जगहों पर 8 मार्च मनाया गया. इन सभाओं में कुल 273 लोगों ने भाग लिया. एरिया पार्टी सचिव ने लोगों को सम्बोधित किया. पितृसत्ता को जड़ से समाप्त करने के लिए महिलाओं के बड़ी संख्या में संघर्ष में उतरने की जरूरत पर जोर देते हुए इन सभाओं का समापन किया गया.

पेरिमिलि इलाके के ताडिगांव रेंज के वट्टिली और बोट्टेनपूंडी गांवों के लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. इस सभा में 110 लोगों ने भाग लिया. कॉमरेड नवीना ने सभा की अध्यक्षता की. कॉमरेड अखिला ने झण्डा फहराया. इस मौके पर महिला मुक्ति की खातिर लड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को लोगों ने दो मिनट की खामोशी मनाकर श्रद्धांजली पेश की. वक्ताओं ने 8 मार्च के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि आज लुटेरे शासक वर्ग भी महिलाओं के हितैषी होने का ढोंग करते हुए 8 मार्च मनाने में लगे हुए हैं ताकि महिलाओं के संगठित प्रतिरोध–संघर्ष को रोका जा सके.

भामरागड़ इलाके में स्थानीय दस्ता और पलटन ने मिलकर 8 मार्च मनाया. इसमें 2 गांवों के करीब 100 लोगों ने भाग लिया. कॉमरेड जानो ने सभा की अध्यक्षता की. पहले झण्डा फहराकर शहीद साथियों के श्रद्धांजली पेश की गई. सभा को दस्ते, पलटन और गांव के जन संगठनों की ओर से अलग–अलग कॉमरेडों ने सम्बोधित किया.

पश्चिम बस्तर डिवीजन

डिवीजन में इस साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस खास तौर पर महिलाओं पर राजकीय हिंसा के खिलाफ मनाया गया. इसके अलावा सरकार के झूठे सुधार कार्यक्रमों, गांवों में जबरिया विवाहों, बाल विवाहों, गांवों में महिलाओं पर मुखियाओं के दबाव के खिलाफ केएएमएस ने बड़ा प्रचार अभियान चलाया. नेशनल पार्क इलाके में पोस्टर–बैनर आदि लगाकर प्रचार किया.

एक–एक रेंज में एक बड़ी सभा आयोजित की गई. केरपे में आयोजित एक सभा में आसपास के 20 गांवों से 2500 लोगों ने भाग लिया. यह आयोजन केएएमएस की रेंज कमेटी की अगुवाई में हुआ था. सभा शुरू होने से पहले लोगों ने एक जोरदार रैली निकाली. इस दौरान सरकारी दमन व झूठे सुधारों के खिलाफ, महिलाओं पर पुरुषों के दबाव के खिलाफ नारे लगाए गए. महिलाओं को जमीन पर अधिकार देने की मांग भी उठाई.

कॉमरेड मासे ने झण्डा फहराकर सभा की शुरूआत की. स्थानीय कमाण्डर ने लोगों को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि गांवों में केएएमएस के गठन के बाद महिलाओं ने कई समस्याओं को लेकर संघर्ष किया. जबरिया विवाहों पर रोक लग गई. उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याएं तभी पूरी तरह हल हो सकती हैं जब इस समाज में शोषण और उत्पीड़न का जड़ से सफाया किया जाएगा. उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि इसके लिए जारी संघर्ष में बड़ी संख्या में शामिल हो जाए. सीएनएम द्वारा पेश सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभा का समापन हुआ.

फरसेगढ़ इलाके के तोयनार गांव में आयोजित सभा में आसपास के 24 गांवों के 3,500 लोगों ने भाग लिया. रैली निकालने के बाद कॉमरेड इडिमे ने झण्डा फहराकर 8 मार्च के महत्व पर रोशनी डाली. बाद में अन्य वक्ताओं ने सभा को सम्बोधित किया. जबरिया विवाह, बाल विवाह, बहु पत्नीत्व, पुलिसिया दमन आदि मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी. सीएनएम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए.

गोडुमंगरू में आयोजित रैली में 350 लोगों ने भाग लिया. पेनकुदुरु में 300 और एडापल्ली में 360 लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. ✶

शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का शहीदी दिवस

20-23 मार्च को साम्राज्यवाद-विरोध दिवस मना

गोदों ने तुझे कल भगत सिंह कहा था ...
कालों ने तुझे आज नक्सली कहा है ...
अवाम तुझे कल भोर का तारा कहेंगे ...
झूलो वे... झूलो वे... झूलो वे...
फांसी के फंदे को चूम कर झोलो...

– महान कवि श्रीश्री

गड़िचिरोली डिवीजन के गट्टा एरिया में एसजेडसी की ओर से जारी पोस्टरों और पर्चों को बड़े पैमाने पर बांटा गया. जन संगठनों ने 22 तारीख की रात में नारगुण्डा, गट्टा और जांबिया गांवों में बैनर बांध दिए. छापामार दलों ने समूचे एरिया में खूब प्रचार अभियान चलाया. पुलिस ने इसे विफल करने की नाकाम कोशिश की.

इस इलाके के पूसगुट्टा गांव में 13 गांवों से आए 760 लोगों ने एक सभा में भाग ली. इनमें महिलाओं की संख्या 200 से ज्यादा थी. सबसे पहले लोगों ने अपने हाथों में बैनर व प्लाकार्ड लेकर गांव के बीच में से एक रैली निकाली. ''भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू अमर रहें'', ''साम्राज्यवाद मुर्दाबाद'', ''इंकलाब जिन्दाबाद'' के नारे जोर शोर से लगाए गए. जुलूस के सभा स्थल में पहुंचने के बाद सीएनएम कलाकारों ने साम्राज्यवाद के विरोध में एक गीत पेश किया. बाद में लोगों को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सुक्कू ने कहा कि साम्राज्यवादियों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को फांसी दी थी, आज उन्हीं साम्राज्यवादियों की मदद से सत्तारूढ़ हुए सामन्ती व दलाल पूंजीपति शासक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वालों की 'नक्सली', 'आतंकी' कहकर मुठभेड़ों में हत्या कर रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह और अन्य क्रान्तिकारियों ने जो संघर्ष शुरू किया वह आज भी समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह आज देश के कोने-कोने में माओवादी क्रान्तिकारियों की अगुवाई में तेज गति से चल रहा है. उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि इस धरती पर से साम्राज्यवाद का जड़ से मिटाने के लिए देश के तमाम नौजवानों को पीएलजीए में भर्ती होना चाहिए. अन्त में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभा समाप्त हुआ.

अहेरी एलजीएस के दायरे में 5 सभाएं आयोजित की गईं जिनमें कुल 13 गांवों के लोगों ने भाग लिया. कुल करीब 600 लोगों ने इस सभाओं में शिरकत की. वक्ताओं ने भगतसिंह की शहादत और देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ गांधी द्वारा की गई गद्दारी के बारे में विस्तारपूर्वक बताया. उन्होंने कहा कि भगत सिंह के अधूरे सपनों को साकार करते हुए भारत की नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाना ही भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजली होगी.

पेरिमिली रेंज के एटापल्ली तहसील के बूरगी गांव में जनता ने 23 मार्च को भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया. इस मौके पर एसजेडसी के आह्वान पर 20 से 23 मार्च तक 'साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस' भी मनाए गए. पूरे इलाके में स्थानीय दस्ते ने पोस्टरिंग किया. 23 मार्च की रात 21 छापामारों और 800 स्त्री-पुरुषों ने हाथों में मशाल, लाल झण्डे, बैनर आदि लेकर ढोलक, कुंडुड आदि पारम्परागत वाद्य यंत्र बजाते हुए रैली निकाली. रैली के दौरान साम्राज्यवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. बस्ती के बीच चौराहे में लाल झण्डा फहराकर शहीदों को श्रद्धांजली पेश की गई. बाद में जुलूस एक बड़ी सभा में बदल गया.

सभा को स्थानीय दस्ता कमाण्डर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ भगत सिंह द्वारा शुरू किया गया संघर्ष आज भी जारी है, अतः इसे और तेज करने की जरूरत है. उन्होंने खासकर अमेरिकी साम्रज्यवाद के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे जन संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवाद भारत और नेपाल में जारी माओवादी संघर्ष को कुचलने के लिए नित नए षड़यंत्र रच रहा है. उन्होंने कहा कि साम्रज्यवाद और उसके इशारों पर चलने वाले भारत के सामन्ती व दलाल पूंजीवादी लुटेरे शासक वर्गों के खिलाफ जारी लोकयुद्ध को तेज करना ही भगत सिंह और उनके साथियों के लिए सच्ची श्रद्धांजली होगी.

एटापल्ली इलाके के कसनसूर रेंज में जनता ने गांव-गांव में साम्राज्यवाद विरोधी दिवस मनाए. पूरे इलाके में 7-8 जगहों पर रैलियां निकाली गईं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया. कोटिमी गांव में 1500, ओडसाटोला में 75, घोटसूर में 150, जेवेली में 200 और कारका में करीब 400 लोगों ने रैलियों में भाग लिया. इनमें महिलाओं और स्कूली बच्चों की संख्या उल्लेखनीय रही. 'भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाल सलाम', 'साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' के नारे लगाए गए.

भामरागड़ इलाके के 5 गांवों की जनता ने 23 मार्च को 'साम्राज्यवाद-विरोध दिवस' मनाया. इसमें 100 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड अर्जुन ने कहा कि महज 24 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो सर्वोच्च कुरबानी दी थी, वह देश के तमाम नौजवानों के लिए आदर्श है. उन्होंने कहा कि दण्डकारण्य में साम्राज्यवादी हमला रोज-रोज बढ़ रहा है. यहां की खनिज सम्पत्ति का दोहन करने के लिए उनकी कम्पनियां यहां तेजी से आ धमक रही हैं जिसका कि हमें जमकर विरोध करना चाहिए. दस्ता कमाण्डर ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि साम्राज्यवाद ने उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण के नाम से दुनिया के गरीब देशों पर जो नीतियां लाद रखी हैं उनके चलते करोड़ों मजदूर-किसानों की जिन्दगी तबाही के कगार पर पहुंच चुकी है. उन्होंने आह्वान किया कि साम्राज्यवाद का सफाया करने सभी तबकों के लोगों को आगे आना चाहिए. ✶

(..... आखिरी पन्ने का शेष)

लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया. इनमें करीब 50 कॉमरेड आन्ध्रप्रदेश में शहीद हो गए. 6 फरवरी को कर्नाटक में हुई एक मुठभेड़ में कॉमरेड साकेत राजन (कर्नाटक राज्य कमेटी का सचिव) शहीद हो गए. उनकी मृत्यु से न सिर्फ कर्नाटक राज्य आन्दोलन को, बल्कि भारत की क्रान्ति को बड़ा नुकसान हुआ है. कर्नाटक की उत्पीड़ित जनता उन्हें एक आदर्शवान क्रान्तिकारी और सर्वहारा बुद्धिजीवी के रूप में हमेशा याद रखेगी. उत्तर तेलंगाना के निजामाबाद जिले के मानाला जंगल में कोवर्ट के जरिए हुए पुलिसिया हत्याकाण्ड में हमारे 10 कॉमरेड शहीद हुए. इनमें जिला कमेटी सचिव कॉ. रमेश और जिला कमेटी सदस्य कॉ. बाबन्ना शामिल हैं. एक और घटना में वरंगल जिले में जिला कमेटी सचिव और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य कॉमरेड यादन्ना शहीद हो गए. झारखण्ड में हमने पीएलजीए के पलटन कमाण्डर कॉमरेड चन्दन को खोया. एक अन्य घटना में एक और पलटन कमाण्डर समेत चार कॉमरेड दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए.

दण्डकारण्य आन्दोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लड़ाई तेज करने के दौरान पिछले एक साल में पार्टी और पीएलजीए के करीब 12 कॉमरेड शहीद हो गए. 17 मई को माड़ डिवीजन के डौला (धौड़ाई) पुलिस कैम्प पर पीएलजीए कम्पनी के द्वारा किए गए हमले के दौरान हमारे चार प्यारे साथी शहीद हो गए. इनमें दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और राज्य सैन्य आयोग सदस्य तथा पीएलजीए की उत्तरी सब-जोनल कमान का कमाण्डर-इन-चीफ कॉमरेड मंगतू (सुनील), सेक्षन कमाण्डर कॉमरेड करुणा (मोती पूनेम) और कॉमरेड विनोद (शिवाजी कुमरम) और कम्पनी सदस्या कॉमरेड सोमारी (पोट्टम रामो) शामिल हैं. इनकी शहादत से हमारे आन्दोलन को बड़ा नुकसान हुआ है. इन कॉमरेडों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बहादुरी के साथ दुश्मन के कैम्प पर धावा बोला था. टोह लेने के दौरान हुई एक तकनीकी गलती से यह हमला सफल न हो सका और हमें यह नुकसान झेलना पड़ा. कॉमरेड मंगतू पिछले 23 सालों से क्रान्तिकारी आन्दोलन में काम कर रहे थे. एक सदस्य से शुरू करके एसजेडसी स्तर के नेता तक उभरे थे. लड़ाई के दौरान बहादुरी, जनता के प्रति सेवा भाव, कॉमरेडों के प्रति आदर, आदि उनके गुण हमारे लिए आदर्श हैं.

इनके अलावा पिछले साल जुलाई में माड़ डिवीजन में हुई एक दुर्घटना में कॉमरेड रानू (गुड्डू) की मृत्यु हुई थी. उसी महीने में पश्चिम बस्तर में कॉमरेड कल्पना की मृत्यु नदी में बह जाने से हुई थी. उत्तर बस्तर डिवीजन में जन मिलिशिया कमाण्डर कॉमरेड प्रेम दुश्मन से हथियार छीनकर लाते समय शहीद हो गए. गड़चिरोली में लगातार जारी शत्रु दमन के बीचोंबीच लड़ाई का परचम ऊंचा उठाते हुए कॉ. भूमन्ना (सेक्षन कमाण्डर), कॉ. सरिता, कॉ. पूसू और कॉ. मासा शहीद हो गए. दक्षिण बस्तर में कॉमरेड विनोद दुश्मन के हाथों मारे गए. पश्चिम बस्तर में मिलिशिया कमाण्डर और एक कॉमरेड की मृत्यु दो अलग-अलग हादसों में हुई. इन सभी कॉमरेडों ने क्रान्तिकारी शूरता का नमूना पेश किया और अपनी शहादत से पीएलजीए की गौरवशाली परम्परा में चार चांद लगाए. इन सभी ने जनता के प्रति अथाह प्रेम और निःस्वार्थता के साथ लड़ते हुए महान आदर्श प्रस्तुत किए हैं.

प्यारे लोगो,

पिछले 25 बरसों से जारी हमारा दण्डकारण्य आन्दोलन आधार इलाके की स्थापना की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है. ग्राम स्तर पर जनता की जनवादी की राजसत्ता के अंगों, यानी 'जनताना सरकार' की स्थापना की जा रही है और उन्हें मजबूत बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं. ग्राम स्तर के बाद एरिया स्तर, डिवीजन स्तर और फिर समूचे दण्डकारण्य स्तर पर 'जनताना सरकार' की स्थापना करके इसे मुक्तांचल में बदलने का लक्ष्य हमें पूरा करना है. देश के कोने-कोने में इस तरह के आधार इलाकों की स्थापना करते हुए देशव्यापी राजसत्ता छीन लेना भारत की नव जनवादी क्रान्ति का मूल उद्देश्य है. पेद्दि शंकर से लेकर मंगतू तक हमारे तमाम प्यारे शहीदों ने इसी सपने को साकार बनाने का प्रयास किया है. हमारे आन्दोलन के विकास में उनकी कुरबानियों का बड़ा योगदान रहा है. इसलिए आज हमारे कंधों पर पीएलजीए को मजबूत कर उसे पीएलए (जन मुक्ति सेना) में तब्दील करने, 'जनताना सरकार' का विस्तार व विकास करने तथा समूचे दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करने का जो अहम व बुनियादी कार्यभार मौजूद है, उसे पूरा करना ही हमारे शहीदों के प्रति सच्चा सम्मान होगा.

पिछले साल 21 सितम्बर को हमारी नई एकीकृत पार्टी के गठन के बाद से दुश्मन डर से कांप रहा है. दूसरी तरफ हमारे पड़ोस के नेपाल में माओवादियों की अगुवाई में जारी जनयुद्ध के उफान को देखकर भारत के शोषक शासक वर्ग काफी परेशान हैं. इसीलिए उन्होंने वामपंथी उग्रवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए देश भर में क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ, साथ ही साथ, दण्डकारण्य आन्दोलन के खिलाफ एक व्यापक और चौतरफा हमला छेड़ दिया है. आधुनिक हथियार, बख्तरबन्द गाड़ियां, सैन्य हेलिकॉप्टर, आदि मंगाए जा रहे हैं. सेना के अधिकारी समय-समय पर दण्डकारण्य का दौरा करके आला पुलिस अफसरों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं. माओवादी आन्दोलन को कुचलने के लिए सेना का भी बहुत जल्द ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे संकेत मिलने लगे हैं. तो हमें आज 'शहीदी सप्ताह' मनाते समय दुश्मन के इस नए हमले को भी परास्त करने का संकल्प लेने की जरूरत है. हमारी पीएलजीए में सैकड़ों-हजारों की संख्या में युवक-युवतियों को शामिल करते हुए, दुश्मन के हथियार छीन कर उसे मजबूत करना होगा. हमारी जन मिलिशिया को एक अपराजेय और मजबूत शक्ति में विकसित करना होगा. हमारे प्यारे शहीदों के हजारों-लाखों वारिस हमें खुद बनना होगा. उनके सपनों के खुशहाल भारत के निर्माण के लिए दृढ़ता से कदम बढ़ाना होगा.

- **गांव-गांव में शहीदों की यादगार में सभा, जुलूस, मशाल जुलूस, रैली आदि का आयोजन करें !**
- **शहीदों की यादगार में स्मारकों का निर्माण करें और जहां पहले से स्मारक बने हुए हैं उनकी मरम्मत करें और उन्हें सुसज्जित करें !**
- **शहीद स्मारकों को तोड़ने के लिए आने वाले पुलिस व सीआरपी बलों को मार भगाएं !**

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

15 जून 2005

भाकपा (माओवादी)

28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाओ !

कॉमरेड चारु मजुमदार

कॉमरेड कन्नाई चटर्जी

हमारे पार्टी के संस्थापक और महान शिक्षक
कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्नाई चटर्जी को लाल सलाम !
डौला हमले में शहीद हुए कॉमरेड्स मंगतू (एसजेडसी सदस्य), करुणा, विनोद और सोमारी को लाल सलाम !!
अपने प्यारे शहीदों के महान उद्देश्य का अभिवादन करो और उसे आगे बढ़ाओ !

प्यारे लोगो,

जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी नई एकीकृत पार्टी – भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने 28 जुलाई को 'शहीदी दिवस' और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक 'शहीदी सप्ताह' मनाने का फैसला लिया है. आगामी 28 जुलाई काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछले साल 21 सितम्बर को सम्पन्न हमारे देश की दो प्रमुख माओवादी पार्टियों के ऐतिहासिक विलय के बाद यह पहला शहीदी दिवस है. हमें इस मौके पर उन तमाम वीर शहीदों को श्रद्धांजली पेश करनी होगी जिन्होंने भारत की नव जनवादी क्रान्ति को सफल बनाने के महान उद्देश्य से अपने प्राणों को न्यौछावर किया है. साथ ही साथ, विश्व समाजवादी क्रान्ति के तहत नेपाल, पेरू, तुर्की, फिलिप्पीन्स आदि देशों में जारी जनयुद्धों में दुश्मन से लड़ते हुए शहीद हुए तमाम वीर योद्धाओं को भी हम इस मौके पर विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजली पेश करते हैं.

इस मौके पर हमारी नई पार्टी के संस्थापक नेता द्वय और हमारे महान शिक्षक कॉमरेड चारु मजुमदार और कॉमरेड कन्नाई चटर्जी को हम जरूर याद करेंगे. हमारे इन प्यारे नेताओं ने भारत के कम्युनिस्ट आन्दोलन में जड़ें जमा चुके संशोधनवाद को तोड़कर भारत की क्रान्ति को एक नई दिशा दी. दीर्घकालिक लोकयुद्ध और कृषि क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध के नियमों को भारत के ठोस हालात में लागू करने में इन दोनों का बड़ा योगदान रहा है. कॉमरेड चारू मजुमदार ने नक्सलबाड़ी संघर्ष का नेतृत्व किया था और भाकपा (मा–ले) की स्थापना की थी. 16 जुलाई 1972 के दिन कोलकाता में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. क्रूर यातनाएं देकर 28 जुलाई के दिन उनकी हत्या की थी. कॉमरेड कन्नाई चटर्जी पूर्व की एमसीसीआई के संस्थापक थे. भारत की क्रान्ति को आगे बढ़ाने हेतु उन्होंने सही लाइन व सही रणनीति–कार्यनीति पेश करके मजबूत नींव डाली थी जिसके आधार पर बिहार–बंगाल समेत देश के कई अन्य इलाकों में एमसीसीआई की अगुवाई में एक बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ. गंभीर अस्वस्थता के चलते 18 जुलाई 1982 को उनका देहान्त मात्र 49 वर्ष की उम्र में हुआ था. इन दोनों नेताओं ने हथियारबन्द क्रान्ति का जो रास्ता पेश किया उस पर आज देश के हजारों–लाखों लोग आगे बढ़ रहे हैं. उनके अधूरे सपनों को पूरा करने कमर कसे हुए हैं.

नक्सलबाड़ी संघर्ष के पहले शहीद बाबूलाल विश्वकर्मा से लेकर आज तक भारतीय क्रान्ति में शहादत की शानदार परम्परा लगातार जारी है. शहीद सप्ताह के इस मौके पर हमें कॉमरेड्स अमूल्य सेन, सरोज दत्त, सुशीतल राय चौधरी, चन्द्रशेखर दास, वेम्पटापु सत्यम, आदिभट्ला कैलासम, पंचादि कृष्णमूर्ति, बूझा सिंह, सुब्बाराव पाणिग्राही, सुदिप्तो बेनर्जी, अप्पू, प्रकाश मास्टर आदि भारतीय क्रान्ति के महान शहीदों को जरूर याद करना चाहिए.

दुश्मन के हाथों क्रूर यातनाएं झेलकर अपना सिर ऊंचा रखकर शहादत की शिखर पर पहुंचने वाले वीर शहीदों में कॉमरेड्स श्याम, महेश, मुरली, पुलि अंजन्ना, भाग्या, सूर्यम, पद्मा, कौमुदी, सुगुना, आदि प्रमुख हैं जिन्हें हम इस मौके पर गर्व से याद करेंगे. 'आसमान का आधा हिस्सा' रखने वाली महिलाओं ने भारतीय क्रान्ति को आगे बढ़ाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिए. इनमें कॉमरेड्स पंचादि निर्मला, स्नेहलता, रजिता, ललिता, चिट्टक्का, पार्वती, कविता, बड़की देवी, उर्मिला, रत्तक्का प्रमुख हैं.

हमारी नई पार्टी के गठन के बाद से अब तक पार्टी, पीएलजीए और जन संगठनों के 70 से ज्यादा कॉमरेड दुश्मन के बलों से वीरतापूर्वक

(शेष पेज 21 पर ....)